बात भारत की

₹50.00

पाञ्चजन्य

21 नवम्बर, 2021

मार्गशीर्ष कृष्ण 2, वि.सं. 2078, युगाब्द 5123

#Bollywood

हर केस को धुएं में उड़ाता चला गया

मुकदमों से बेपरवाह, चटपट 'न्याय' पाने में माहिर और नशे के महिमामंडन में मदहोश मायानगरी पर छलकने लगा है समाज का आक्रोश





बात भारत की

पाञ्चजन्य

वर्ष 73, अंक 24, मार्गशीर्ष कृष्ण 2, वि.सं.- 2078
(युगाब्द 5123) 21 नवम्बर, 2021
आईएसएसएन : 2349-2392

संपादक : हितेश शंकर
सहयोगी संपादक : संदीप त्रिपाठी
सहयोगी संपादक : आलोक गोस्वामी
समाचार संपादक : अरुण कुमार सिंह
मुख्य उपसंपादक : नागार्जुन
वरिष्ठ संवाददाता : अश्वनी मिश्र
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर : शशि मोहन रावत
सीनियर ग्राफिक डिजाइनर : मुक्ता सूरमा कटारिया
कला संयोजन : मंगल सिंह नेगी, राजपाल सिंह रावत, जनार्दन सिन्हा

E-mail: editor.panchjanya@gmail.com
Website: www.panchjanya.com

सम्पादकीय विभाग दूरभाष: 8860874360

भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड

प्रबंध निदेशक : भारत भूषण अरोड़ा
मुख्य महाप्रबंधक : आशीष कुमार खरे (cgm@bpdl.in)
महाप्रबंधक : शोनाल गुप्ता (shonal.gupta@bpdl.in)
निदेशक एवं प्रकाशक : बिहारीलाल सिंघल

विज्ञापन विभाग

मोबाइल : 708-9696-708 ईमेल : advt@bpdl.in

प्रसार विभाग

प्रसार, अभियान, एजेंसी, बुक स्टाल एवं थोक ग्राहक
मोबाइल : 972-7979-972
ईमेल : circulation@bpdl.in

नई सदस्यता, शिकायत और अन्य सहायता के लिए
मोबाइल : 814-3232-814
ईमेल : support@bpdl.in

पंजीकृत कार्यालय
संस्कृति भवन, 2322, लक्ष्मी नारायण गली
पहाड़गंज, नई दिल्ली-55

गुजरात कार्यालय
बी-1, परव अपार्टमेंट, एल.जी. अस्पताल के पीछे, मुक्ति मैदान
मणिनगर, अमदाबाद-380008, गुजरात
संपर्क : 9426170862

लखनऊ ब्यूरो
ब्यूरो चीफ : सुनील राय
कार्यालय: विश्व संवाद केन्द्र, भूतल, डॉ. एम.सी. पंत मार्ग
लोहिया पथ, जियामऊ, लखनऊ-226001

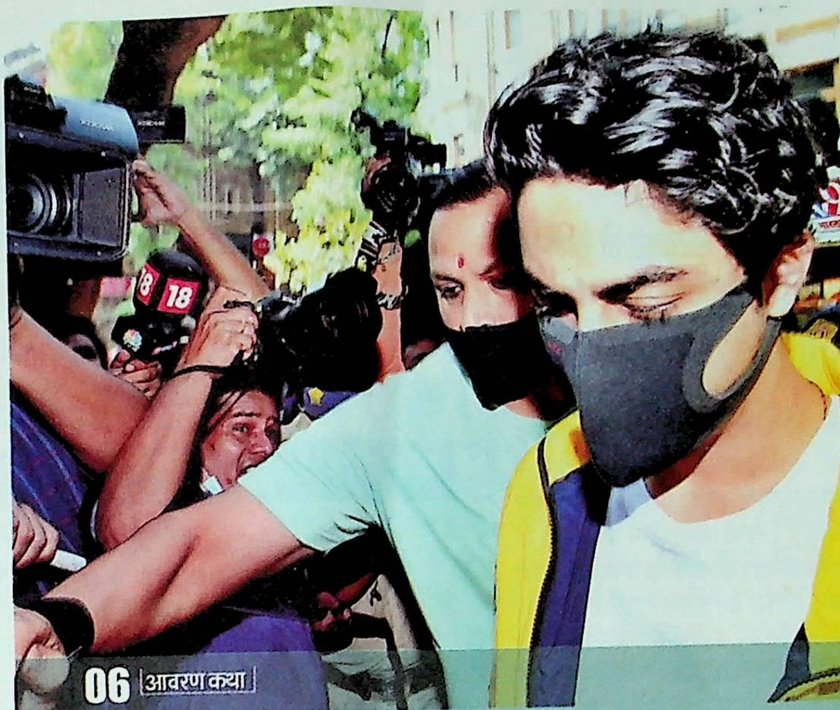
उत्तराखंड ब्यूरो
ब्यूरो चीफ : दिनेश मानसेरा
कार्यालय: 163, पाल्म सिटी, रामपुर रोड
हल्द्वानी, उत्तराखंड-263139

बेंगलुरु ब्यूरो
कार्यालय: विक्रमा प्रकाशन, न. 106, 5 मेन रोड
पोस्ट बाक्स न. 1804, चामराज पेट, बेंगलुरु-560018

संवाददाता: केरल-तिरुअनंतपुरम-प्रदीप कृष्णन
दूरभाष-0471-2732476, बिहार-पटना-संजीव
कुमार-दूरभाष-09430002248.

मुद्रक एवं प्रकाशक बिहारीलाल सिंघल द्वारा भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड के लिए संस्कृति भवन 2322, लक्ष्मी नारायण गली, पहाड़गंज नई दिल्ली-55 से प्रकाशित तथा एचटी मीडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, (उ.प्र.) 201306 से मुद्रित। संपादक : हितेश शंकर

इस अंक में



06 आवरण कथा

हर केस को धुएं में उड़ाता चला गया

बॉलीवुड में नशे और अपराध को महिमामंडित किया जा रहा है। मायानगरी के कलाकार न सिर्फ परदे पर नशे का सेवन करते और गीत गाते दिखते है बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी नशे के लती हो चुके हैं और इसकी स्वीकारोक्ति भी वे खुल कर करते हैं। पकड़े जाने पर मुकदमे से बेपरवाह हैं और चटपट न्याय पाने में माहिर हैं। इससे समाज का आक्रोश छलकने लगा है

अपनी बात	5	हितेश शंकर
सम्मान का बढ़ा मान	16	प्रमोद जोशी
असाधारण प्रतिभा, साधारण लोग	22	अजय विद्युत
लेते हो चंदा, बताओ जरा धंधा	32	डॉ. अजय खेमरिया
उसका दाग, इसके माथे	35	पाञ्चजन्य ब्यूरो
सनातन एकता के प्रतीक हैं तीर्थस्थल	36	डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन
घुसपैठ और कब्जे को कानूनी जामा	40	आदर्श सिंह
सादगी, संयम और सेवा के प्रतीक	43	संजीव कुमार
बारूद के ढेर पर है सीपीईसी	44	अरविन्द

स्तंभ 4 आजकल 46 संस्कृति संवाद 48 तकनीक

आज-कल

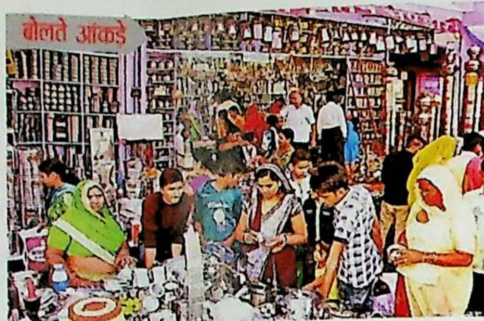
केंद्र-पंजाब सरकार में तकरार



पंजाब में बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र को 15 से बढ़ाकर 50 किमी. करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले को पंजाब और पुलिस का अपमान करार दिया है। पंजाब सरकार इसके खिलाफ न्यायालय भी जाएगी। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र का समर्थन करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

दुबई एयर शो में हिस्सा लेगी भारतीय वायु सेना

भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी 14 से 18 नवंबर तक अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर होने वाले दुबई एयर शो में हिस्सा लेगी। यूएई सरकार ने भारतीय वायु सेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीमों के साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये टीमें सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और यूएई के अल फुरसान सहित दुनियाभर की कुछ बेहतरीन एरोबेटिक्स और डिस्प्ले टीमों के साथ प्रदर्शन करेंगी। इसमें सारंग टीम के पांच उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव, सूर्य किरण टीम के 10 बीएई हॉक 132 और तीन एलसीए तेजस शामिल होंगे। इससे पहले सारंग टीम ने 2005 में यूएई में अल ऐन ग्रांड प्रिक्स में भाग लिया था। इस बार सूर्य किरण और तेजस पहली बार अपना कौशल दिखाएंगे।



बोलते आंकड़े

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 55 प्रतिशत बढ़ा है, जो बीते वर्ष समान अवधि में 46.6 प्रतिशत घटा था। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान आर्थिक सुधार में गति आई है और दीवाली पर 1.3 लाख करोड़ रु. की बिक्री हुई, जो इस दशक में सबसे अधिक है।

आमने - सामने



यमुना में जो झाग है, वह ओखला बैराज इलाके में है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। इसलिए यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी योगी सरकार नाकाम रही है। यह प्रदूषित पानी दिल्ली का नहीं है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाला तोहफा है।

—राघव चड्ढा, अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड



भगीरथ जी स्वर्ग से गंगा को बादलों के जिस मार्ग से उतार कर लाए थे, 'लघुकाय-लंपट' जी, यमुना जी को उसी रास्ते दिल्ली ले आए हैं और वह भी 'मुफ़्त'। और हां, इस बार वायु-प्रदूषण की जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों पर रहेगी, पंजाब वालों पर नहीं, क्योंकि वहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं।

—कुमार विश्वास, कवि

(दिल्ली जलबोर्ड के अध्यक्ष शायद यह भूल गए कि यमुना दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर बहती है)

100 साल बाद कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा



भारत से 100 साल पहले चोरी कर कनाडा भेजी गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में बाबा दरबार क्षेत्र में प्रतिमा की अगवानी कर इसे स्थापित करेंगे। पुनर्स्थापना यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए 13 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। अलग-अलग स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता व श्रद्धालु फूलों की वर्षा करेंगे तथा पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण व आरती करते हुए प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। यह मूर्ति 18वीं सदी की है, जिसे 1913 में काशी के घाट से चुराकर कनाडा भेज दिया गया था। वहां पर यह मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना यूनिवर्सिटी के संग्रह का हिस्सा थी।

साइबर गुटरगूं



हरियाणा में डीएपी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र से बातचीत करके अतिरिक्त रैक देने की मांग की गई है। अगले 4 दिन में प्रदेश को 16 अतिरिक्त रैक मिल जाएंगे, जिससे जिलों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाएगी। उपायुक्तों को खाद वितरण की लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए हैं।

—मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हजारों सालों से कुछ लोग हिंदुत्व को भला-बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अलग-अलग नाम दे रहे हैं। ऐसे भटके हुए प्राणियों को या तो माफ कर देना चाहिए या नजरअंदाज। ये नहीं जानते कि ऐसे मौकों पर हिंदुत्व और भी मजबूत होता है, क्योंकि हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है।

—अनुपम खेर, अभिनेता

पंजाब की नयी पटकथा

■ हितेश शंकर

पंजाब में ताजा राजनीतिक उठापटक भारतीय राजनीति के नए समीकरण गढ़ेगी या सिर्फ एक प्रान्त तक सीमित रहेगी? यह तो कैप्टन अमरिन्दर सिंह थे जो पार्टी और परिवार के प्रति निष्ठा और समर्पण के कारण धैर्य का परिचय देते रहे वरना उपेक्षा और अपमान के छींटों से अलगाव का घड़ा तो कब का भर चुका था!

अब ढहती कांग्रेस को उसके पारम्परिक गढ़ गिने जाने वाले प्रान्त में कद्दावर सेनापति की चुनौती के निहितार्थ गहरे हैं।

पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की 'लॉलीपॉप पॉलिटिक्स' की नई दस्तक को किनारे रख दें तो अखाड़े में तीन गंभीर खिलाड़ियों को गिना जाना चाहिए।

पहला -शिरोमणि अकाली दल, जो अपनी पंथिक पहचान और बादल कुनबे की पुरानी मजबूत पकड़ के कारण पंजाब की राजनीति में हमेशा एक पक्ष रहा है।

दूसरी- कांग्रेस, जो वहां क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के पहले से है। और जिसका एक तय, बंधा वोटबैंक यहां लगाातार रहा है।

और तीसरी -भाजपा। जो अबतक राष्ट्रीय स्तर की पहचान और नेतृत्व होने के बाद भी राज्य में गठबंधन धर्म निभाते हुए झुककर चल रही थी। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर भाजपा ने क्षेत्रीय विस्तार के संकल्प को जता दिया है।

पंजाब की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि तीन प्रमुख दलों में से दो ऐसे हैं जिनके बारे में विश्लेषक मानते हैं कि बेटों ने परिवार केंद्रित दल और राजनीति का आधार बिगाड़ा है। एक, राहुल गांधी, जिनका रवैया अड़ियल न होता और हल्के अप्रभावी नेताओं को वरिष्ठ समर्पित नेताओं पर वरीयता देने की उनकी जिद न होती तो पंजाब कांग्रेस में बिखराव का ऐसा विस्फोट ना होता।

दूसरे, सुखबीर सिंह बादल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 'बड़े बादल' के कमान छोड़ने के बाद से भ्रष्टाचार के आरोप, मनमानी और पुराने नेताओं के साथ समीकरणों को बिगाड़कर रखने से दल के लिए दलदल बढ़ी है।

ऐसे में यह कहने की जरूरत नहीं कि तीसरा कोण कैप्टन अमरिन्दर मजबूत करेंगे। निश्चित ही अमरिन्दर सिंह की शक्ति अभी इतनी नहीं लगती कि वे अपने बूते पूरे राजनीतिक समीकरण का कायापलट कर दें। मगर जो तीसरा कोण उभर रहा है जहां कांग्रेस से भी छिटकाव है और शिरोमणि अकाली दल से भी, उस तीसरे कोण को मजबूत करने का काम कैप्टन करेंगे।

इसलिए दलों की राजनीति के अतिरिक्त पंजाब में अमरिंदर सिंह होने के अर्थ को समझना ज्यादा आवश्यक है।

वे सैनिक हैं - कैप्टन उनके नाम के साथ लगा तमगा है।

सिक्ख रेजिमेंट के कैप्टन के नाते वर्ष 1965 में भारत- पाक युद्ध में योगदान की उनकी पृष्ठभूमि है।

वे सिख हैं -और यह नहीं भूलना चाहिए कि सूबे की राजनीति में हुए ताजा बदल के समय कांग्रेस नेतृत्व ने भी कहा था कि अमरिंदर के विकल्प में भी उसे कोई केशधारी सिख ही चाहिए। यानी कि सूबे में पंथिक पहचान की ताकत कैप्टन के पास ही है।

तिस पर वे जट्ट सिख हैं - यानी जाट और सिख का समीकरण साधती पहचान। क्या आप जानते हैं इस समय अखिल भारतीय जाट महासभा का अध्यक्ष कौन है? अमरिंदर सिंह।

देखना यह होगा कि कांग्रेस से किनारा करने के अमरिन्दर के निर्णय का असर क्या हरियाणा और उससे परे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी होगा? यह तथ्य है कि कथित किसान आंदोलन की बात करने वाले 'आन्दोलनजीवी' भी अमरिन्दर के खिलाफ कोई कड़ी या कड़वी बात कहने का साहस अबतक नहीं जुटा पाए हैं क्योंकि उनके जनाधार को वे लोग भी जानते हैं। उनकी अन्य विशेषता यह भी है कि वे खरी बात कहते हैं, डरते नहीं हैं और किसी की कृपा पर आश्रित नहीं हैं। यानी बैसाखी पर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े नेता हैं।

अमरिंदर सिंह प्रकरण के बाद कांग्रेस के लिए यह कहना उचित होगा कि राहुल गांधी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। मगर राहुल होने का अर्थ यह है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी एक बार नहीं, बल्कि बार-बार मारी जा सकती है। और उनके पास ऐसी 'कॉमरेड कोटरी' है जो पांव पर कुल्हाड़ी मारने को भी उनकी रणनीति बता सकती है। हेमंत बिस्वसरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और अब अमरिन्दर सिंह के उदाहरण बताते हैं कि कांग्रेस की डाल को काटने का राहुल का खेल जारी है। देखना यह है कि पंजाब में सियासत की जो नई पटकथा लिखी जा रही है, उसका व्याप सिर्फ सूबे तक रहेगा या वहां से राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव पैदा करने वाली तरंगें निकलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, सब उस कहानी के कहे जाने का व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं।

@hiteshshankar



क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की याचिका को उच्च न्यायालय में तरजीह दी गई

हर केस को धुएं में उड़ाता चला गया

बॉलीवुड में नशे और अपराध को महिमामंडित किया जा रहा है। न्यायालयों द्वारा इस पर ध्यान न दिए जाने से आम लोगों में धारणा बन रही है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि देश का कानून और विधि प्रणाली धनवानों और ताकतवर लोगों का पक्ष लेती है।

■ अनूप भटनागर



न्यायिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिखना चाहिए कि न्याय किया गया। दूसरा, कानून सभी के लिए समान है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है। उच्चतम न्यायालय भी बार-बार इसी पर जोर देता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? पहली नजर में तो यही महसूस होता है कि ये सिद्धांत किताबी हैं। अगर व्यक्ति संपन्न और प्रभावशाली है तो उससे संबंधित मामले को प्राथमिकता मिलती है।



सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह ने एक निर्णय में कहा था कि देश में ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर, शक्तिशाली और राजनीतिक पहुंच वालों के लिए एक व्यवस्था और संसाधनों से वंचित आम आदमी के लिए दूसरी व्यवस्था हो।

संजय दत्त से लेकर आर्यन खान तक, सिने जगत की हस्तियों के मामले में तो ऐसा ही देखने में आया है। कई राजनेता, उनकी संतानें, उद्योगपति और पत्रकार भी आपराधिक मामलों में अपनी सम्पन्नता और पहुंच की नुमाइश करके आम आदमी की तुलना में कहीं जल्दी न्यायालय से राहत प्राप्त कर चुके हैं। संविधान में भले ही नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का प्रावधान हो, लेकिन आम नागरिक इसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इसीलिए सामान्यतया आम नागरिक कोर्ट-कचहरी के झंझट से बचने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय तो जल्द मिलेगा नहीं और इसमें पैसा और समय जरूर बर्बाद हो जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की हालिया टिप्पणी कुछ हद तक आम नागरिकों की इस तरह की आशंकाओं की पुष्टि करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आम आदमी को अदालतों में आने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति जनता की आस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह, न्यायालय ने हाल ही में अपनी एक व्यवस्था में दोहराया है कि देश में कानून सभी के लिए एक समान है और गरीबों तथा अमीरों के लिए अलग-अलग कानून नहीं हो सकते। न्यायालय की यह व्यवस्था सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? शायद नहीं।

जमानत के मामलों में ही नहीं, बल्कि भांति-भांति के मुकदमों में अक्सर यह देखा गया है कि गरीब व्यक्ति को न्याय के लिए कई-कई बरस ठोकरें खानी पड़ती हैं, जबकि साधन संपन्न और अमीर वर्ग के वादकारियों के मामले में ऐसा नहीं होता।

शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह ने जुलाई, 2021 में एक फैसले में कहा था कि देश में ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर, शक्तिशाली और राजनीतिक पहुंच वालों के लिए एक व्यवस्था और संसाधनों से वंचित आम आदमी के लिए दूसरी व्यवस्था हो। न्यायाधीशों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता दीपक चौरसिया की हत्या के मामले में बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत रद्द करते हुये यह टिप्पणी की थी।

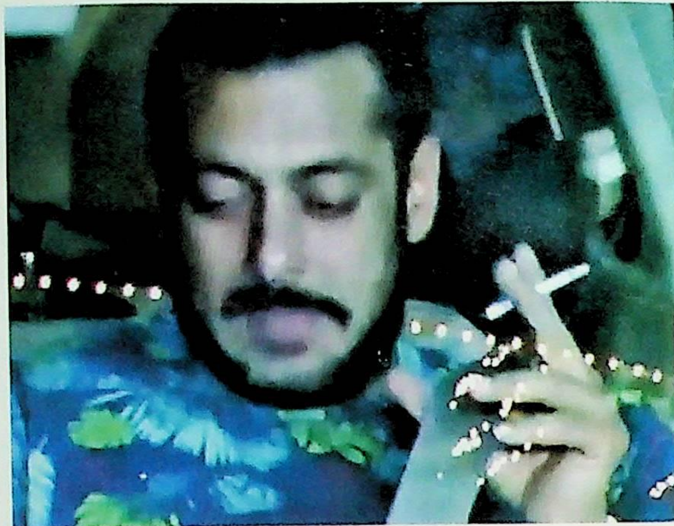
इसके विपरीत, शीर्ष अदालत के ही एक पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता का मानना है कि देश के कानून और विधि प्रणाली धनवानों और ताकतवर लोगों का पक्ष लेती है। न्यायमूर्ति गुप्ता मई 2020 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि जब कोई धनवान या ताकतवर व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है तो वह मुकदमा लंबित होने के दौरान तेजी से सुनवाई का आदेश प्राप्त होने तक बार-बार उच्च अदालतों का दरवाजा खटखटाता रहता है। उनका कहना था कि ऐसा गरीब वादकारियों की कीमत पर होता है, जिनके मुकदमे लटकते रहते हैं, क्योंकि वे ऊपरी अदालत तक नहीं जा सकते।

संजय दत्तः इस संबंध में अयोध्या में 2 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस के बाद मुंबई में 12 मार्च, 1993 को सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए। इन घटनाओं के बाद एके-47 राइफल रखने के आरोप में 19 अप्रैल, 1993 को टाडा के तहत गिरफ्तार किए गए सिने





सलमान खान



अब एक अन्य सुपर स्टार सलमान खान के मामले पर नजर डालें तो पाएंगे कि राजस्थान में काले हिरण के शिकार से लेकर हिट एंड रन की घटना में उनके मुकदमे को प्राथमिकता मिली। काले हिरण के शिकार का मामला तो बार-बार कानूनी दांव-पेचों में उलझता रहा है। सलमान खान पर आरोप था कि सितंबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में उन्होंने सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ दो काले हिरणों का शिकार किया था। इस संबंध में सलमान के खिलाफ चार मामले दर्ज हुए थे। उन्हें 12 अक्तूबर, 1998 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तत्काल ही जमानत मिल गई। इसके बाद भी उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन जमानत मिल गई थी। इस मामले में 8 साल बाद पहला फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 फरवरी, 2006 को सुनाया। इसमें सलमान को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद, एक अन्य फैसला 10 अप्रैल, 2006 को आया, जिसमें अदालत ने वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि शस्त्र कानून के तहत दर्ज मामले में वह बरी हो गए थे। सलमान से जुड़ा सबसे दिलचस्प मामला 28 सितंबर, 2002 का मुंबई के बांद्रा पश्चिम में हिट एंड रन का है, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया गया था। इस मामले में सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता को 6 मई, 2015 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।

अदालत के फैसले के बाद सलमान को तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन उसी दिन शाम को आनन-फानन में बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी। इस तरह यह अभिनेता जेल जाने से बच गया था। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के 6 मई, 2015 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर तत्परता से सुनवाई की और 10 दिसंबर, 2015 को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. जोशी ने अपने फैसले में कहा कि सलमान खान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अभियोजन इन आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। हिट एंड रन प्रकरण में सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराये गए सलमान खान को उसी दिन उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिलना धनवान और प्रभावशाली लोगों को अदालत से जल्दी राहत दिलाने की धारणा को बल प्रदान करता है। इस मामले में तो एक तथ्य यह भी है कि सत्र अदालत की सजा के खिलाफ सलमान की अपील पर उच्च न्यायालय में मात्र सात महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि घटना के समय सलमान खान न तो शराब के नशे में थे और न ही वह गाड़ी चला रहे थे। यहां सवाल यह है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा था? इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सिपाही तथा मुख्य गवाह रविन्द्र पाटिल और हादसे के शिकार लोगों के बारे में सवाल तो उठे, लेकिन जवाब नहीं मिले।

अभिनेता संजय दत्त का ही मामला लें। बंबई उच्च न्यायालय ने एक महीने से भी कम समय के भीतर 5 मई, 1993 को संजय दत्त को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। लेकिन इसी दौरान बम विस्फोट की घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया और इसी दौरान टाडा अदालत ने 4 जुलाई, 1994 को संजय दत्त की जमानत रद्द कर उसे जेल भेज दिया था।

पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए कठोर कानून टाडा में गिरफ्तार किसी भी आरोपी के लिए जमानत पाना आसान नहीं था। इस वजह से अनेक युवक इस कानून के तहत पंजाब की जेलों में बंद थे। टाडा मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती थी। संजय दत्त के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि विशेष अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। उनकी जमानत का मामला शीर्ष अदालत में आने पर न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह की पीठ ने टाडा कानून-1987 से जुड़े कतिपय सवाल 18 अगस्त, 1994 को संविधान पीठ के पास भेजे थे। इन सवालों पर विचार

आर्यन खान

अब अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान का मामला लें। आर्यन को एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में 2 अक्तूबर की रात को हिरासत में लिया था। मादक पदार्थों के गोरखधंधे की चपेट में आए आर्यन को छुड़ाने के लिए पिता शाहरुख खान ने देश के जाने-माने वकीलों की सेवाएं लीं। इसका लाभ यह हुआ कि 20 अक्तूबर को विशेष अदालत से जमानत पाने में असफल रहे आर्यन खान के वकीलों की टीम ने तत्काल ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर तत्परता से सुनवाई हुई और 14 शर्तों पर उसे 28 अक्तूबर को जमानत मिल गई। आर्यन की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के एक मंत्री नवाब मलिक से लेकर तमाम चैनलों में ऐसी बेचैनी फैली मानो एनसीबी ने किसी निर्दोष को जान-बूझकर गिरफ्तार कर लिया है। कुछ मीडिया संस्थानों ने अदालत की हर क्षण की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और प्रकाशन करने में भी संकोच नहीं दिखाया। स्थिति का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उच्च न्यायालय से जमानत का एक पंक्ति का आदेश आने के बाद चैनलों ने ऐसी व्याख्या की, जैसे पूरा आदेश ही उनके हाथ में आ गया है। हकीकत यह है कि आर्यन की जमानत की शर्तें ही 29 अक्तूबर को मुहैया कराई गई थीं, जबकि विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब यह फैसला तो आगे चलकर होगा कि आर्यन खान को विशेष अदालत आरोप मुक्त करती है या उन पर पूरी तरह से मुकदमा चलेगा।

इस मामले में आर्यन को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा के साथ क्रूज से हिरासत में लिया गया था। इन तीनों को विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब आर्यन ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की तो इस तरह के तमाम मामलों की तुलना में उनकी याचिका को तरजीह दी गई और न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने इस पर सुनवाई की। हालांकि, दो अधिवक्ताओं ने आर्यन की अपील को वरीयता दिए जाने पर न्यायमूर्ति साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर न्यायमूर्ति साम्ब्रे की टिप्पणी थी कि यह शिकायत रुचिपूर्ण नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि क्या कोई शिकायत भी रुचिकर हो सकती है?

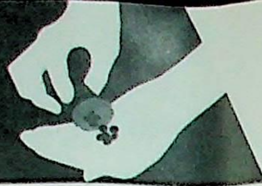
भारती सिंह

हास्य कलाकार भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया का मामला तो और भी दिलचस्प है। इस दंपती को तो दो दिन में ही अदालत से जमानत मिल गई थी। दोनों को एनसीबी ने 21 नवंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इनके घर और कार्यालय से 86 .5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अदालत ने दंपती को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में दे दिया था। इसी बीच भारती सिंह और हर्ष ने जमानत अर्जी दायर की और विशेष अदालत ने 23 नवंबर को दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत की राय थी कि एनडीपीएस कानून के तहत यह मात्रा कम थी।



के लिए तत्काल न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ। इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अहमदी (बाद में प्रधान न्यायाधीश बने), न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा (बाद में प्रधान न्यायाधीश बने), न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत, न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह शामिल थे। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति वर्मा ने 9 सितंबर, 1994 यानी एक महीने से भी कम समय के भीतर टाडा कानून के तहत जमानत से संबंधित बिंदुओं पर विचार करके अपनी सुविचारित व्यवस्था दे दी थी।

संजय दत्त का मामला सामने आने पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सितंबर, 1994 को टाडा के तहत आरोपियों की जमानत पर रिहाई के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रतिपादित कर दिए थे। इस व्यवस्था के बाद ही 16 अक्तूबर, 1995 को उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने संजय दत्त को पुणे की यरवदा जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, टाडा अदालत ने बाद में 28 नवंबर, 2006 को अपने फैसले में संजय दत्त को टाडा के तहत दर्ज आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन उन्हें शस्त्र कानून के तहत दोषी ठहराया था। अंततः उच्चतम



रिया चक्रवर्ती



बॉलीवुड के ही उभरते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून, 2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर भी कई सवाल उठे थे। इन्हीं सवालों के बीच शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस मामले में मादक पदार्थों के सेवन और आपूर्ति जैसे पहलुओं की जांच के लिए एनसीबी की भी मदद ली गई। एनसीबी ने रिया चक्रवती को मुंबई में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोप में 8 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे निचली अदालत से जमानत नहीं मिली। हालांकि, बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने एनसीबी की सारी दलीलों को अस्वीकार करते हुए रिया चक्रवर्ती को 8 अक्तूबर, 2020 का जमानत दे दी। लेकिन न्यायालय ने 4 सितंबर को गिरफ्तार रिया के भाई शौविक और एक कथित माल पहुंचाने वाले (पेडलर) अब्दुल बासित परिहार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अरमान कोहली



इससे कुछ अलग मामला एक और अभिनेता अरमान कोहली का है, जो इतने खुशनसीब नहीं थे। अरमान कोहली को एनसीबी ने 28 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 1.2 ग्राम कोकीन मिली थी, जबकि इससे ज्यादा मात्रा में मादक पदार्थ इस मामले के सह-आरोपी से मिला था। अरमान कोहली की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में कहीं कोई हंगामा नजर नहीं आया। स्थिति यह है कि विशेष अदालत ने 14 अक्तूबर को कोहली की जमानत याचिका रद्द कर दी और उसकी अपील पर अभी तक उच्च न्यायालय में भी सुनवाई नहीं हुई है।

न्यायालय ने 21 मार्च, 2013 को संजय दत्त की पांच साल की कैद की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें चार सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया था।

यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि नवंबर 2020 में रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय में प्राथमिकता पर सूचीबद्ध किए जाने पर भी सवाल उठे थे। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर अर्णब की जमानत याचिका सुनवाई के लिए अगले ही दिन सूचीबद्ध करने पर सवाल उठाए थे। दुष्यंत दवे ने यह लिखने में भी संकोच नहीं किया था कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जैसे प्रतिष्ठित वकील की याचिका भी तत्काल सूचीबद्ध नहीं हो सकी थी और उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। ■





नशे के शिखर पर सितारे

बॉलीवुड में ड्रग्स और नशे के आम हो जाने की बातें अब दबी-छिपी नहीं रह गई हैं। फिल्मों में भी नशे का महिमामंडन करते सीन और गीत बहुतायत में हैं। इसके साथ ही अपराध और माफिया का भी महिमामंडन दिखता है। ऐसे दृश्यों या उदाहरणों से उनकी मुरीद युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है, इससे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बेफिक्र हैं तो समाज आक्रोशित

■ विशाल ठाकुर

यदि एक आम आदमी के नशे में धुत्त होने या ड्रग्स लेने की बात सार्वजनिक हो जाए तो क्या होगा? वह अपनी नौकरी खो सकता है, परिवार बर्बाद हो सकता है और यहां तक कि उसका सामाजिक बहिष्करण हो सकता है। परंतु यदि आप फिल्मी सितारे हैं तो ड्रग्स का सेवन न केवल सिर उठाकर कर सकते हैं, बल्कि आपके आभामंडल के पीछे यह काला कृत्य ऐसे छिप जाएगा कि किसी को कभी नजर नहीं आएगा। नशे की ऐसी आजादी किसी अन्य भारतीय के पास तो नहीं दिखती। हालांकि पूरी फिल्म बिरादरी तो नशेड़ी नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि हर फिल्म स्टुडियो, फिल्म सेट आदि पर ड्रग्स आसानी से मिल जाता है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नशा-ड्रग्स और इनके सेवन से बॉलीवुड सितारों का दशकों से गहरा याराना रहा है। नशे और नशीले पदार्थों का महिमामंडन करने वाली फिल्मों के निर्माण में हर किसी ने बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया है। हालांकि यह अंतर करना मुश्किल है कि इसका असर उनकी निजी जिंदगियों पर भी पड़ा है या निजी जिंदगियों की रंगीली रातों और जश्न का असर ही बॉलीवुड की फिल्मों और गीतों पर पड़ा है। क्योंकि नशे में धुत्त दिखते फिल्म सितारों की पार्टीज की वीडियोक्लिप्स तो ऐसा ही कुछ दर्शाती हैं, जो आज सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

फिल्मी गीतों में नशे का घोल

हम सब इस तरह के गीतों से परिचित हैं और बेबस हैं अपने लाडले और लाडलियों को इन पर थिरकते देखने के लिए। चार बोतल वोदका, काम मेरा रोज का..., हां मैं अल्कोहॉलिक हूं.... सरीखे गीत बताते हैं कि नशेड़ी होना और नियम से शराब का सेवन करना कितने गर्व की बात है। शराब के गीतों से दिल ऊब जाए तो चरस-गांजे और



सुट्टे को समर्पित गीत हाजिर हैं।बाबाजी की बूटी... और मनाली ट्रांस... के जरिये ड्रग्स की ट्रेनिंग ली जा सकती है और बदनामी के लिए तो बाबाजी हैं ही। मैं टल्ली हो गई..., दारू देसी..., मैं शराबी..., हमकोपीनी है..., छोटे-छोटे पेग..., टल्ली हुआ..., रम एंड व्हिस्की..., दारू पीके डांस..., दारू विच डांस... इत्यादि गीतों की पूरी श्रृंखला है, जो यह दर्शाती है कि नशे से सराबोर गीतों और इस थीम पर आधारित फिल्मों का भविष्य बॉलीवुड में सदैव उज्जवल रहा है। अतीत में झांककर देखें तो दम मारो दम..., प्यार दो प्यार लो.. मुझे पीने का शौक नहीं... पीले-पीले ओमेरे राजा..., एक-एक हो जाए...जैसे गीत मिलते हैं।

दरअसल, अब जाकर फिल्मों के माध्यम से बड़ी आसानी और सहजता से शराब पीने का सामान्यीकरण कर दिया गया है, साथ ही पार्टी गीतों के नाम पर शराब के साथ-साथ अन्य मादक पदार्थों जैसे चरस, गांजा वगैरह को भी सामान्य जनजीवन का हिस्सा बनते देखा जा सकता है। दर्शक एक ही समय में यह देखकर हैरान हो सकते हैं कि एक तरफ कई बॉलीवुड सितारे ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा देती फिल्मों और गीतों का हिस्सा बने नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ से नोटू ड्रग्स की तख्ती थामे समाजसेवा की नौटंकी करते भी दिखते हैं।

मौजूदा दौर की फिल्मों में शराब के सेवन का चित्रण आम बात हो गया है। वह दौर गया जब फिल्म सेट पर शराब की बोतलों की खेप पर विलेन और उसके गुर्गों का ही एकाधिकार होता था। मौका लगा तो हीरो ने दो-चार पेग उड़ा लिये। इससे ज्यादा पेग हीरो ने उड़ाये तो समझें कि बात दिल टूटने पर आ गई है। सन् 1959 में फिल्म मैं नशे में हूं का नायक मोहन खन्ना (राज कपूर) नशे में होने की तसकीद तोकर रहा है, साथ ही माफी भी मांग रहा है। मुकेश की आवाज में इस फिल्म का गीत मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं... ब्लैक एंड व्हाइट रील पर फिल्माया गया एक महफिल वाला गीत है। आज के दौर में इस गीत का रीमेक या कहिए, रीमिक्स वर्जन बनाया जाए तो कैसे बनेगा, आप समझ सकते हैं। थोड़ा-सा और आगे बढ़ने पर दिलीप कुमार की फिल्म लीडर (1964) का गीत मुझे दुनियावालो शराबी ना समझो... याद आता है। श्वेत-श्याम से ईस्टमैन कलर यानी रंगीन पिक्चर के दौर में आलीशान पार्टीज के माहौल में फिल्माया गया यह गीत भी एक पार्टी गीत था, जो शराब के नाम पर शर्मिंदा तो कतई नहीं करता।

ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं जब किसी वजह से शालीनता के साथ शराब या नशे का जिक्र किसी गीत में किया गया। फिर बाद की फिल्मों में पार्टी के दृश्यों, बिगड़ैल बेटा और समाज से ठुकराया कोई सज्जन सुरा सेवन को आतुर दिखाई देने लगा। शुरुआती फिल्मों में शराब की तस्करी, विलेन के अड्डे पर शराब के साथ ग्लैमर इत्यादि को जोड़ा गया। हिप्पी कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति और नशे की गिरफ्त में आई युवा पीढ़ी पर आधारित देव आनंद की फिल्म *हरे रामा हरे कृष्णा* (1971) में नशे से दूर रहने की बात पर बल दिया गया और बाद की फिल्मों में यानी अस्सी के दशक के आस-पास देसी शराब के भट्टे और फिर जहरीली शराब के दुष्परिणामों को भी दिखाया जाने लगा। यही वह दौर था जब फिल्मों की थीम में शराब तो थी, लेकिन चरस-गांजे के साथ हेरोइन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थ भी व्यापक रूप से दिखाई देने लगे थे।

इसी दौर में आई संजय खान की फिल्म *काला धंधा गोरे लोग*





(1986), फिरोज खान की जांबाज (1986) और अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी (1984)। संजय और फिरोज की फिल्मों में ड्रग्स की तस्करी और सेवन पर जोर था, जबकि बिग बी नाचती बोतल के जरिए मसाला मनोरंजन परोसते दिखे। लेकिन अब तक भी शराब की बात घर के बाहर की बात थी। लेकिन मिलेनियम की शुरुआत के साथ आई आमिर खान की फिल्म मेला (सुपर फ्लॉप) ने मानो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अपने भाई के साथ उन्होंने शराब कोकोला के माफिक पिया है। बाद में रही-सही कसर आयुष्मान खुराना की फिल्म *विक्की डोनर* से पूरी होगई, जिसमें एक बहू और सास रोज सांझ ढले पेग लड़ाने बैठ जाती हैं।

रीति-रिवाज मंडली ने इस चलन का खुले दिल से स्वागत किया। नतीजतन आयुष्मान की एक अन्य फिल्म *ड्रीमगर्ल* (2019) में अम्माजी के रूप में एक ऐसा ही किरदार देखने को मिला। पूरी बोतल गटकने को आतुर दिखाई देने वाली एक बुजुर्ग महिला के इर्द-गिर्द कॉमेडी का ताना-बाना बुना गया और लोग इसे सहजता से पचाते गए।

मुझे याद आता है दि कपिल शर्मा का एक एपिसोड जिसमें कपिल शर्मा, गेस्ट रैप सिंगर योयो हनी सिंह से चार बोतल वोदका गीत की पंक्तियों का राज पूछते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनी सिंह ने क्या जवाब दिया, मोटी बात यह है कि शराब की बोलतों को केन्द्र रखकर ये सारी बातें एक ऐसे मंच पर हो रही थीं, जिसे करोड़ भारतीय परिवार देखते हैं। बाद में किसी ने नहीं बताया कि हनी सिंह इतने साल कहां गुम रहे। इतना ही सामने आ सका कि वे बाईपोलर विकार से जूझ रहे हैं। जरा सोचिए कि जब ऐसे गीत गाने वाले को ऐसे विकार से जूझना पड़ा तो उसके गीतों को सुन-सुनकर युवा पीढ़ी के न जाने कितने लाड़ले-लाड़लियों को कैसे-कैसे विकारों से गुजरना पड़ा होगा। यहां अकेले हनी सिंह नहीं हैं। शराब की बोतल में स्याही डाल लगभग सभी नशीले गीत लिख रहे हैं।

हां, मैंने ड्रग्स ली है

अलग-अलग मौकों पर कई बॉलीवुड सितारों ने कबूल किया है कि वे नशे के आदी रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त वर्षों तक नशे के आदी रहे। अपने कई साक्षात्कार में उन्होंने नशे के सेवन की बात को माना। हालांकि बाद में उन्होंने नशा करने से तौबा कर ली और एक साफ-सुथरा जीवन बिताने के लिए प्रतिबद्ध हुए। नरक के नौबरस, जी हां, वह अपने नशे के दिनों को इसी नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि वह कोकीन और हेरोइन जैसे ड्रग्स के आदी थे और इनसे छुटकारा पाने के लिए टैक्सास के किसी रिहैब सेंटर में दस वर्ष तक रहे।

ताजा प्रकरण की बात करें तो अभिनेता अरमान कोहली का नाम ड्रग्स से जुड़ा पाया गया है। उनके घर से नशीले पदार्थ बरामद भी हुए हैं। वह अब जेल में हैं और बेल के लिए गुहार लगा रहे हैं। बीते साल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशे के ऐंगल के जांच कर रही एनसीबी अभिनेता अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ कर चुकी है। इस प्रकरण में एनसीबी अर्जुन की प्रेमिका एवं लिव-इन पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स और उसके भाई अगिसियालोस डेमेट्रिएड्स से भी पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरोकोअगिसियालोस के पास से हशीश और नशीली दवाओं की गोलियां (एल्प्राजोलम) बरामद हुई थीं और इसके बाद ही अर्जुन से पूछताछ की गई थी।

फिल्म में कोई अश्लील सीन हो तो आप चैनल बदल देंगे, लेकिन उस गीत का क्या जिसे बच्चे कहीं भी सुन और देख सकते हैं। नशे और शराब को बढ़ावा देते ऐसे गीत हम जैसे अभिभावकों की चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। स्थिति तब और अटपटी होजाती है, जब बच्चे हमारे माता-पिता के सामने चार बोतल वोदका... गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे गीत बनने ही नहीं चाहिए।

– संजय जैन, बिजनेसमैन, नोएडा, उत्तर प्रदेश

ऐसे गीत पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन बहुत कम। और बने भी तोएक सभ्यता के दायरे में ताकि समाज या किसी वर्ग पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन अब तोहद हो गई है। नाती-पोते जब नशे पर आधारित ऐसे गीतों पर हमारे सामने डांस करते हैं तोआंखें शर्म से झुक जाती हैं। उन्हें कैसे समझाएं हम लोग। लेखकों कोइस पीढ़ी कोभटकने से रोकना चाहिए।

– अशोक शर्मा, सेवानिवृत सरकारी अधिकारी, रोहिणी, दिल्ली

हम देखते हैं कई फिल्मों में सब ठीक होता है, लेकिन ड्रग्स या नशे के अत्याधिक और गहन चित्रण के चलते फिल्म को ए या यूए सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हमें महसूस होता है कि इससे बचा जा सकता है। नशे के खिलाफ लड़ाई में जागरुकता जरूरी है। लेकिन हमें किसी चीज के महिमामंडन की बारीक लकीर कोपहचानना होगा।

– संजय शर्मा, एडवायजरी पैनल सदस्य, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

ये समझ से परे है कि किसी गैंगस्टर पर फिल्म क्यों बनाई जाए। उसने समाज को क्या दिया है। हमारे देश में हर क्षेत्र में इतनी प्रबुद्ध हस्तियां रही हैं कि अगले सौ वर्ष तक भी फिल्में बनाते रहे तोकम न पड़ें। धर्म, समाज, वीरों और समयकाल को लेकर भारत में विषयों की कोई कमी है क्या। माफिया, ड्रग्स और नशे की फिल्मों का चित्रण बंद होना चाहिए।

– विशाल जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उदयपुर, राजस्थान

गंदे शब्दों वाले गीतों का सबसे ज्यादा खामियाजा शायद महिलाओं कोही भुगतना पड़ता है। कोई सड़क पर भद्दा गीत गाकर फब्ती कस देगा। और बाद में ये चिंता कि कहीं बच्चा ये सब न सीखने लगे। सिनेमा का काम मनोरंजन करना है न कि कदम-कदम पर चुनौतियां पेश करना।

– माधवी ठाकुर, गृहिणी, दिल्ली

और फिर किसी सिंडिकेट की तरह कई कड़ियां खुलने लगीं। यह भी सामने आया कि अगिसियालोस उन ड्रग्स पेडलर्स से जुड़ा रहा है, जिनसे कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती, शौविक, दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदे थे। यह सब बीते साल नवंबर माह की घटनाएं हैं और उन्हीं दिनों निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी सबीना सईद कोभी एक मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें अगले दिन जमानत मिल गई थी। इस बीते साल में ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के संबंध में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह आदि से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके कुछ दिन बाद टीवी की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाछिया के अंधेरी स्थित घर पर छापा मारा गया, जहां से बताया जाता है कि ८६.50 ग्रा. गांजा बरामद किया गया था।

और ज्यादा पीछे जाकर देखें तो साल 2001 में अभिनेता फरदीन खान को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक जमाने में मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोईराला कोभी कुछ समय के लिए ड्रग्स की आदत लग गई थी। पूजा भट्ट भी कभी शराब की लत में थीं। इसी प्रकार से प्रतीक बब्बर भी बहुत छोटी उम्र में ड्रग्स लेने लग गए थे। एक इन्टरव्यू में रणबीर कपूर ने कबूल किया था कि फिल्म *रॉकस्टार* की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स ली थी। कंगना रानावत भी यह खुलासा कर चुकी हैं कि तनाव के दिनों में वह कभी ड्रग्स लिया करती थीं, लेकिन बाद नें उन्होंने इससे दूरी बना ली। नब्बे के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम भी ड्रग्स माफिया के साथ जुड़ा पाया गया।

क्लिप्स ने खोली कलई?

मगर यह बात कभी सामने नहीं आती कि बॉलीवुड की हाई सोसाइटी में रंगीली रातों में क्या-क्या गुल खिलाए जाते हैं। पर तकनीक का यह ऐसा युग है, जहां कुछ भी नहीं छिपता। बीते साल इन्हीं दिनों की बात है, जब बॉलीवुड और नशे के बीच संबंधों की परतें उधेड़ी जा रही थीं। तभी एक वीडियोक्लिप सामने आई, जो कथित तौर पर निर्माता करण जौहर की पार्टी की बताई जाती है। इस क्लिप में बॉलीवुड सितारे जैसे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, मीरा राजपूत, शकुन बत्रा,





हमारे फिल्म सितारों कोसोचना चाहिए कि जिस तरह से युवा पीढ़ी उनके फैशन ट्रेंड्स कोअपना लेती है, ठीक वैसे ही कुछ अन्य बातों कोभी बिना कुछ सोचे-समझे फॉलोकरने लगती है। फिल्म सितारों द्वारा परदे पर या परदे के बाहर नशा करना या नशे से उनका जुड़ना, ऐसे खबरें युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। बॉलीवुड कोइसका ध्यान रखना होगा।

— **अभिजीत सावंत**, नौकरीपेशा, मुंबई



एक अध्यापक होने के नाते हमारी चिंता और बढ़ जाती है कि हम विद्यार्थियों को नशे की तरफ जाने से कैसे रोकें। ऐसे में शराब और नशे कोबढ़ावा देते गीत मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसे गीतों के बोल के साथ-साथ उनका फिल्मांकन भी काफी उत्तेजक होता है और आजकल तोछोटी उम्र के बच्चे भी सब कुछ आसानी से कहीं भी देख सकते हैं। ये वाकई काफी चिंताजनकक है।

— **अतिरेक गौड़**, टीचर, दिल्ली

मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। साफ दिखता है कि कैसे ये सारे सितारे नशे में धुत्त हैं। कह नहीं सकते कि शराब के नशे या ड्रग्स के नशे में। लेकिन यह वीडियो बताता है कि इन पार्टियों में क्या होता है। बीते साल इस वीडियोके सामने आने के बाद काफी हो-हल्ला भी हुआ था, जिसके संबंध में करण जौहर ने सफाई दी थी कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया था औरर बाद में एफएसएल रिपोर्ट में भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी।

माफिया की बड़ाई

शायद ज्यादातर लोगों को अंत तक समझ नहीं आएगा कि साल 2017 में आई फिल्म *हसीना पारकर* क्यों बनाई गई थी। मुंबई बम कांड सहित भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले कुख्यात आतंकी दाउद इब्राहिम की बहन की जीवनी पर फिल्म बनाने का आइडिया कौन से सावन में सूझा होगा, कहा नहीं जा सकता। शायद श्रद्धा कपूर ने यह भूमिका इसलिए निभाई हो कि वह नहीं करेंगी तो कोई और कर लेगा। बॉलीवुड की यही रीत है। क्या एक भी ऐसा कलाकार होगा, जिसने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया हो कि फिल्म का संबंध दाउद और उसकी बहन से है, इसलिए वह फिल्म में काम नहीं करेगा? खैर, साल 2017 तक भी हमारे कई फिल्मकारों को यही लगता होगा कि देश में प्रेरणादायी हस्तियां और महान वीरों की गाथाओं की कमी है, इसीलिए वह माफिया सरगनाओं और कुख्यातों पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन अब यह भ्रम और कथित रूप से फैलाया गया मायाजाल टूट रहा है।

अब फिल्मकारों के पास *हसीना पारकर* जैसी फिल्म के जवाब में बाटला हाउस (2019) जैसी फिल्म भी है, जो गुणगान करती है अपने वीर सपूत स्व. संजीव कुमार यादव का जिनकी दिल्ली के बटला हाउस कांड में दिए गए बलिदान कोकभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि माफिया और उनके सरगनाओं की बड़ाई का

बॉलीवुड की यही रीत है। क्या एक भी ऐसा कलाकार होगा, जिसने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया हो कि फिल्म का संबंध दाउद और उसकी बहन से है, इसलिए वह फिल्म में काम नहीं करेगा? साल 2017 तक भी हमारे कई फिल्मकारों को यही लगता होगा कि देश में प्रेरणादायी हस्तियां और महान वीरों की गाथाओं की कमी है, इसीलिए वह माफिया सरगनाओं और कुख्यातों पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन अब यह भ्रम और कथित रूप से फैलाया गया मायाजाल टूट रहा है।

यह सिलसिला काफी पुराना है और मुनाफा देने वाला भी है। तभी तो मुंबई के एक नहीं दो-दो बड़े माफियाओं पर एक के बाद एक फिल्म बनीं। कोई बता सकता है कि हाजी मस्तान और दाउद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित बताई गई साल 2010 में आई अजय देवगन और इमरान हाशमी की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई या इसकी सीक्वल फिल्म *वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा* 2013 में आई जिसमें अक्षय कुमार और इमरान खान की मुख्य भूमिका थी, से दर्शकों को क्या हासिल हुआ? यही कि किसी अबोध बालक ने डॉन बनने तक का सफर कैसे तय किया?

शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) हो या *शूटआउट एट वडाला* (2013), संजय दत्त की *वास्तव* (1999) हो या राम गोपाल वर्मा की *कंपनी*, बॉलीवुड फिल्मकारों ने माफिया को बड़े ही अच्छे तरीके से भुनाया है। खासतौर से राम गोपाल वर्मा ने, जिन्होंने *सरकार, सरकार राज, डी कंपनी, सत्या, डी*, अब तक 56, कॉन्ट्रैक्ट, शबरी, डिपार्टमेंट, सत्या 2, सरकार 3 सरीखी माफिया वाली फिल्मों से लंबे समय तक अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ बहुत पहले ही कर लिया था। बाकियों की दाल आजकल गल नहीं रही है।



सम्मान का बढ़ा मान

साल, 2014 के बाद पद्म सम्मानों के जरिए देश ऐसी विभूतियों के दर्शन कर पा रहा है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में अद्‌भुत कार्य कर रहे हैं। यह सभी वे गुमनाम हस्तियां हैं, जिन्होंने हर कार्य के लिए सरकारों की ओर नहीं ताका बल्कि अपनी धुन और लगन से कुछ करके दिखाया

■ प्रमोद जोशी



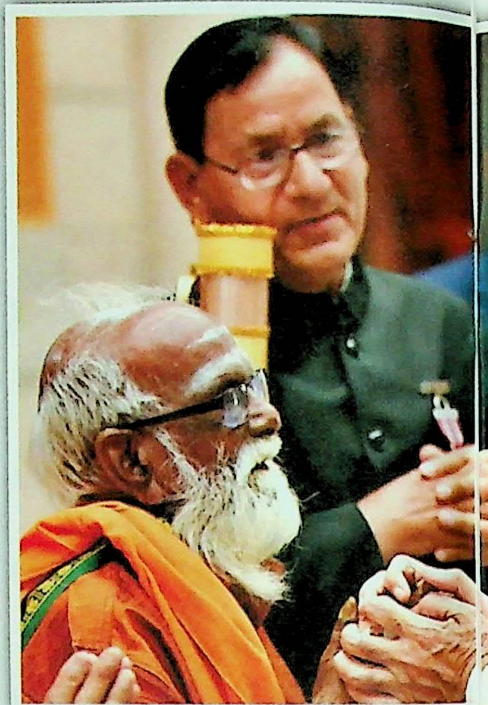
राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों के साथ (मध्य में) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं पत्नी सविता कोविंद। साथ में हैं उपराष्ट्रपति सर्वश्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह

सोमवार 8 और मंगलवार 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्पन्न पद्म सम्मान वितरण समारोह में इस बार कुछ ऐसी हस्तियां थीं, जिन्हें देखकर हर्ष और विस्मय दोनों होते हैं। इसमें एक थे कर्नाटक से आए हरेकला हजब्बा। साधारण कपड़े पहने हजब्बा पद्मश्री पुरस्कार लेने नंगे पांव आए थे। जब उन्हें सम्मान-पत्र दिया गया, तब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे सड़क के किनारे संतरे बेचते थे। जिस गांव में पैदा हुए वहां स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए। उन्होंने ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरे बेचकर पाई-पाई जुटाए पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोला, जो आज 'हजब्बा आवारा शैल' यानी हजब्बा का स्कूल के नाम से जाना जाता है।

इसी समारोह में कर्नाटक की 72 वर्षीया वनवासी महिला तुलसी गौडा पद्मश्री सम्मान लेने नंगे पांव आई थीं। तुलसी गौडा पिछले छह दशक से पर्यावरण-संरक्षण की अलख जगा रही हैं। कर्नाटक के एक गरीब वनवासी परिवार में जन्मीं तुलसी कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन उन्हें जंगल के पेड़-पौधों, जड़ी-बूटियों के बारे में इतनी जानकारी है कि उन्हें 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट' कहा जाता है। हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा ने 12 साल की उम्र से अब तक कितने पेड़ लगाए, गिनकर वे बता नहीं सकतीं। अंदाजा लगाती हैं शायद चालीस हजार, पर असली संख्या शायद एक लाख से भी ऊपर है। उनके सम्मान में हॉल में उपस्थित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर तमाम अतिथि हाथ जोड़े खड़े थे।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की वनवासी महिला





पद्म सम्मान प्राप्त हस्तियों का अभिनंदन करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

राहीबाई सोमा पोपेरे भी पद्मश्री ग्रहण करने आईं। उन्हें 'सीड मदर' के नाम से जाना जाता है। 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूहों के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। दो दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज वे सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए जैविक खेती करती हैं।

सम्मानित होने वालों में अयोध्या से आए मुहम्मद शरीफ भी थे, जो अपने ढंग से समाज सेवा में लगे हैं। हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके समाजसेवी मुहम्मद शरीफ को निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 25,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 वर्ष पूर्व उनके एक जवान बेटे की कहीं सड़क दुर्घटना से मौत हो गई थी। घरवालों को इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाई और पुलिस ने लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद से मुहम्मद शरीफ ने निश्चय किया कि मैं लावारिसों का वारिस बनूंगा। आर्थिक तंगी के बावजूद वे इस जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं।

अभिजात्य से हटकर

जब सम्मानों की बात होती है, तब सम्मानित लोगों की जो छवि हमारे मन में बनी है, उससे कुछ अलग किस्म के लोगों को सम्मानित होते देखकर मन प्रफुल्लित होता है। यह असली भारत का सम्मान है, साथ ही बदलते भारत की तस्वीर। यह उन लोगों का सम्मान है, जो अपनी धुन और लगन से काम करते चले आ रहे हैं। ये हैं इस देश के वास्तविक नायक।

आम धारणा रही है कि पद्म सम्मान ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं, जिनकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच हो। पर भारत सरकार के इस नए चलन से धारणा बदलेगी। देश के वास्तविक नायकों को खोजना और उन्हें सम्मानित करना बड़ी बात है। अभिजात्यवाद से हटकर उन जमीनी लोगों को खोजना जो इस देश के वास्तविक रत्न हैं। ऐसे रत्नों की कमी नहीं है। उन्हें खोजने की जरूरत भर है।

पद्म सम्मानों के माध्यम से, सरकार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, जनसेवा, लोक सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देती है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से पद्म सम्मानों से कई गुमनाम नायकों को सम्मानित कर रही है, जो विभिन्न तरीकों से समाज में योगदान दे रहे हैं। सामान्यतः इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी यह पहली पहचान ही होती है।





अब उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे नायकों की न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि उन्हें उच्चतर श्रेणियों के सम्मान भी मिलेंगे। सम्मानों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 जनवरी को की जाती है और सम्मान-समारोह अप्रैल में होता है। महामारी के कारण 2020 और 2021 के पुरस्कार तय समय पर नहीं दिए जा सके थे, इसलिए 2020 और 2021 दोनों साल के पद्म विजेताओं को इस साल एक साथ सम्मानित किया गया। यह समारोह इसीलिए दो दिन चला।

सम्मानों की बात जब होती है, तब सम्मानित लोगों की जो छवि हमारे मन में बनी है, उससे कुछ अलग किस्म के लोगों का सम्मान देखकर मन प्रफुल्लित होता है। यह असली भारत का सम्मान है, साथ ही बदलते भारत की तस्वीर।

पारंपरिक कौशल

अच्छी बात यह है कि अब देश का कोई भी नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का अनुमोदन कर सकता है, जिसे वह सम्मान का पात्र समझता है। यह व्यवस्था 2017 से शुरू हुई है। इसी वजह से पिछले पांच वर्ष से ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब सम्मानित हो रहे व्यक्ति केवल दिल्ली या उसके आसपास के लोग ही नहीं हैं। सुदूर पूर्व और दक्षिण के लोगों की संख्या भी बढ़ी है। संगीत, कला, दस्तकारी और समाज सेवा के क्षेत्रों में शास्त्रीय कलाओं के साथ-साथ लोक-कलाओं और पारंपरिक-कौशलों से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं।

सन् 2017 में देश ने केरल की मीनाक्षी अम्मा का नाम सुना। 75 वर्षीया मीनाक्षी गुरुक्कल यानी मीनाक्षी अम्मा, परंपरागत युद्ध-कौशल कलारीपयट्ट में सिद्धहस्त हैं। कलारीपयट्ट तलवारों और लाठियों से खेला जाने वाला केरल का प्राचीन 'मार्शल-आर्ट' है। उस साल के पद्म सम्मान पाने वालों में उनके अलावा तेलंगाना के खम्मम जिले के रेड्डिपल्लि गांव के 84 वर्षीया दरिपल्ली रमैया का नाम भी था, जो एक करोड़ से अधिक पौधों को पेड़ बना चुके हैं। दरिपल्ली रमैया को लोग 'ट्री मैन' के नाम से जानते हैं। वे बीज बोकर पौध उगाते हैं और फिर उसे रोपकर बच्चे की तरह देखभाल करके पेड़ बनाते हैं।

पद्म सम्मान नहीं मिलता तो लोग गिरीश भारद्वाज के बारे में नहीं जान पाते। कर्नाटक के गिरीश भारद्वाज ने दूरदराज के गांवों में कम लागत से और पर्यावरण के अनुकूल सवा सौ से ज्यादा पुल तैयार किए हैं। उन्हें 'सेतु-बंधु' के नाम से जाना जाता है। उसी साल इंदौर की 91 वर्षीया डॉक्टर दादी भक्ति यादव को पद्म सम्मान मिला, जो



कर्नाटक की तुलसी गौड़ा की सादगी ने न केवल राष्ट्रपति भवन में सबका मन मोहा बल्कि प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री तक उनको प्रणाम करते नजर आए

1940 से मरीजों का मुफ्त इलाज करती रहीं थी। इस सम्मान के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। इस देश में ऐसी तमाम महान विभूतियां हैं, जिनका समय रहते सम्मान होना चाहिए।

पुरस्कारों की राजनीति

18 अगस्त, 2007 को जब दशरथ मांझी का दिल्ली में कैंसर से लड़ते हुए निधन हुआ था, तब उसके जीवट और लगन की कहानी देश के सामने आई थी। पर तब किसी ने नहीं कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे अभिजात्य मन में यह बात नहीं आती थी। 16 नवंबर, 2013 को सचिन तेंदुलकर ने प्रतियोगी क्रिकेट से जिस दिन संन्यास लेने की घोषणा की, उसी रोज भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। उनके साथ प्रसिद्ध गणितज्ञ सीएनआर राव को भी भारत रत्न दिया गया। दोनों की महानता पर कोई शक नहीं, पर सम्मानों को लेकर एक बहस तब चली थी, जिसके कुछ मुद्दे तब महत्वपूर्ण थे और आज भी प्रासंगिक हैं।

दिन-प्रतिदिन के अनुभव भी हमारी रीति-नीति को तय करते हैं। इन सम्मानों के माध्यम से देश की वास्तविक प्रतिभा को सामने आने का जो अवसर अब मिल रहा है, वह प्रशंसनीय है। यह परंपरा आगे बढ़नी चाहिए।

सचिन तेंदुलकर देश की पहचान हैं। उनकी प्रतिभा और लगन युवा वर्ग को प्रेरणा देती है। सहज और सौम्य हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, मां का सम्मान करते हैं और एक साधारण परिवार से उठकर आए हैं। इन सभी कसौटियों पर वे श्रेष्ठ हैं, पर उन्हें सम्मान देने वालों ने इन कसौटियों पर उन्हें सम्मानित किया था क्या? शायद ऐसा 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। यह तय करने का कोई मापदंड नहीं है कि वे देश के सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं भी या नहीं। कुछ और खिलाड़ी भी इस सूची में हैं। मसलन ध्यानचंद। ध्यानचंद महान खिलाड़ी थे, और उस दौर में थे जब हमें आत्मविश्वास की जरूरत थी। फिर भी वे लोकप्रियता के उस शिखर पर नहीं थे, जिस पर सचिन तेंदुलकर रहे। तब वह मीडिया भी नहीं था, जो व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है। हमने उन्हें सम्मान दिया है। ध्यानचंद के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरी तरफ देखें कि सचिन को लोकप्रिय बनाने वाली एक पूरी कारोबारी मशीनरी थी। यह सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि हमारे समाज ने ध्यानचंद को इतना लोकप्रिय क्यों नहीं बनाया कि वे 1955 में ही भारत रत्न होते? भारत रत्न महात्मा गांधी भी नहीं बने, पर वे नेहरू से छोटे नेता भी नहीं थे।

सचिन तेंदुलकर को लोकप्रिय बनाने वाले और ध्यानचंद को लोकप्रियता के शिखर पर न लाने वाले राज-समाज के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। इस विचार से ध्यानचंद निरर्थक हैं। भीड़ उन्हें पहचानती नहीं, भले ही वे महान थे। हमने इस भीड़ को उनकी महानता से परिचित ही नहीं कराया। अच्छी बात यह है कि

खिलाड़ियों को भारत रत्न का सम्मान भी मिलने लगा, जो उसके पहले संभव नहीं था।

सम्मान हैं, खिताब नहीं

कुछ लोग अपने नाम के पहले पद्मश्री वगैरह लगाकर घूमते हैं। अदालतें और सरकारें यह चेतावनी देती रहती हैं कि इनका इस्तेमाल नाम के साथ खिताब की तरह नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अच्छी तरह स्थापित होनी चाहिए कि पद्म सम्मान अंग्रेजी सरकार के खिताबों जैसे नहीं हैं। बालाजी राघवन/ एसपी आनंद बनाम भारतीय संघ, (1995) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सम्मान हैं खिताब नहीं। सत्यपाल डांग ने सन् 2005 में जब पद्मभूषण सम्मान लौटाया तब उन्होंने उसकी गरिमा गिरने के साथ-साथ इस बात का जिक्र भी किया कि लोग अपने नाम के पहले पद्मश्री, पद्मभूषण वगैरह लगाते हैं, जो नैतिक और कानूनी रूप से गलत है।

राजेन्द्र प्रसाद पर अपनी नर्स को और राजीव गांधी पर अपने स्कूल-प्रिंसिपल को पद्मश्री देने का आरोप लगा। यह भी कि राजीव ने तमिल वोट पाने की खातिर एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न दिलाया। भीमराव आंबेडकर को भारत रत्न मिलने पर वीपी सिंह पर 'दलित वोट' की राजनीति का आरोप लगा। सन् 2010 में अमेरिका में होटल चलाने वाले संत सिंह छटवाल को जब पद्मभूषण मिला, तब भी वह विवाद का विषय बना।

आचार्य जेबी कृपालानी ने सन् 1969 में ऐसे सम्मानों को खत्म करने के लिए लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया था। वह पारित नहीं हो सका। इसके एक साल पहले हृदय नारायण कुंजरू ने भारत रत्न देने की सरकारी पेशकश को ठुकराया था। सरकारी प्रतिनिधियों को यह अनुमान नहीं था कि संविधान सभा के सदस्य के रूप मेंउन्होंने ऐसे सम्मानों का विरोध किया था। सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब अलंकरणों को खत्म करने का फैसला किया गया। मोरारजी देसाई व्यक्तिगत रूप से अलंकरणों के खिलाफ थे। संयोग है कि 1991 में मोरारजी को भारत रत्न का अलंकरण दिया गया। दूरदर्शन ने जब मोरारजी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, ''मैं ऐसे अलंकरणों के खिलाफ हूं, पर आप देना ही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।''

शैक्षिक और सैन्य-श्रेष्ठता

संविधान का अनुच्छेद 18(1) कहता है ''राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान (एकैडमिक ऑर मिलिटरी डिस्टिंक्शन) के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।' संविधान सभा में प्रोफेसर केटी शाह ने अनुच्छेद 12 का समर्थन किया था, जो बाद में अनुच्छेद 18 बना। आमराय थी कि सरकार अंग्रेज सरकार की तरह खिताब और उपाधियां नहीं देगी। संविधान सभा की राय थी कि सरकार को खिताब देने ही नहीं चाहिए। क्या इन सम्मानों को रणक्षेत्र की बहादुरी और विद्या से जुड़ी श्रेष्ठता से जोड़ा जा सकता है?

सन्, 1955 में सरकारी आदेश के रूप में इन्हें शुरू किया गया था। यह बहस चलती रही है और शायद चलती रहेगी कि पद्म सम्मान विद्या, कौशल या सेवा-संबंधी अन्य सम्मानों जैसे हैं। सच यह है कि अतीत में काफी वाजिब लोग सम्मानित हुए हैं, पर यह भी सच है कि सम्मान पाने के इच्छुक लोगों की लाइन लगती रही है। अच्छी बात यह है कि अब ऐसे नाम सुनाई पड़ने लगे हैं, जो वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों पर संविधान सभा में विचार हो सका होगा। दिन-प्रतिदिन के अनुभव भी हमारी रीति-नीति को तय करते हैं। इन सम्मानों के माध्यम से देश की वास्तविक प्रतिभा को सामने आने का जो अवसर अब मिल रहा है, वह प्रशंसनीय है। यह परंपरा आगे बढ़नी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)



असाधारण प्रतिभा साधारण लोग

जो लोग कल तक अपने शहर में अनजान से थे, समाज जिन्हें हाशिए पर समझता रहा, वे सभी आज सुर्खियों में हैं। पद्म सम्मान प्राप्त ये वे लोग हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और अपनी लगन और जिजीविषा से किया अद्भुत काम

■ अजय विद्युत

पद्म सम्मान पहले भी दिए जाते थे। 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन वे ज्यादातर सरकारी समारोह में अभिजात्य वर्ग तक सीमित थे। वही पद्म सम्मान अभी भी दिए जा रहे हैं- लेकिन इन सम्मान को 'जनता के पद्म' में बदलने के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता और संकल्प दिखाया था, उसका असर साफ नजर आ रहा है। केवल नीयत का फर्क है। और जो सम्मान सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के इर्द-गिर्द मंडराने वाले या उनके जानने वालों तक सीमित रहे थे, वे अब आम नागरिक तक पहुंच गए हैं। पहले पद्म सम्मान की सिर्फ खबरें छपती थीं, अब देश के नागरिकों में चर्चा का विषय बनते हैं। लोग उन पर बात करते हैं। समाज के हाशिए पर रहकर भी असाधारण काम करने वाले लोगों को अब नोटिस किया जा रहा है। वे पूरे राष्ट्र में वास्तविक नायकों के रूप में उभर रहे हैं।

अभी 2020 के लिए 141 और 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए पद्म विभूषण से 7, पद्मभूषण से 16 और पद्मश्री से 118 लोगों को सम्मानित किया गया, जबकि 2021 के लिए 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मान प्रदान किए गए। सम्मान वितरण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,''मुझे यह देख कर खुशी हुई कि जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को जनता की भलाई के लिए उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए पहचाना जा रहा है। उन सभी को बधाई।'' प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति के बारे में जानें और उनसे प्रेरित हों।

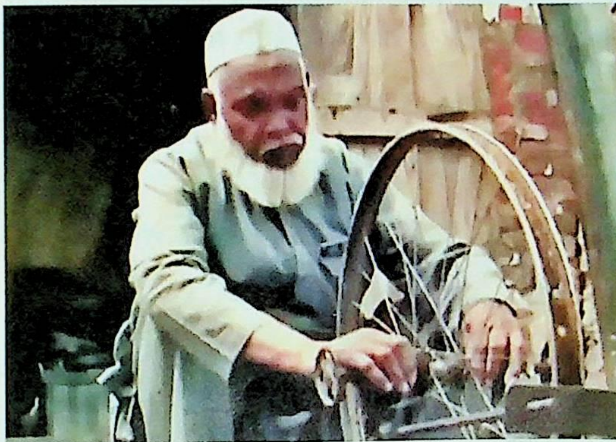
सताई जा रही महिलाओं की मदद



झारखंड के महतो सरीकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में बिरबांस पंचायत है। वही के गांव भोलाडीह की रहने वाली हैं **छूटनी देवी**। आशा (एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस) के सौजन्य से वे महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र चलाती हैं। उन्हें समाज के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों हेतु 2021 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। छूटनी देवी का संगठन उन महिलाओं की सहायता करता है जिन्हें समाज में डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। वे तमाम ऐसी अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण सताई गई महिलाओं की मदद करती हैं। उन्हें या उनके संगठन के लोगों को जैसे ही यह सूचना मिलती है कि कहीं किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है- वे अपनी टीम

के साथ वहां पहुंच जाती हैं और महिला को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करवाती हैं। छूटनी देवी स्वयं भी समाज द्वारा बेवजह प्रताड़ित की गईं। फिर उन्होंने ऐसी तमाम महिलाओं की मदद का संकल्प लिया। 1995 की बात है। एक तांत्रिक के कहने पर छूटनी देवी को डायन मान लिया गया था। इसके बाद उन्हें मल खिलाने और मूत्र पिलाने की कोशिश की गई। पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। वे किसी तरह अपनी जान बचा जंगलों की ओर भाग निकली। उसके बाद वे ज्यादती करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास गई तो पुलिस ने ना रिपोर्ट लिखी, ना उनकी कुछ मदद की। तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे तमाम प्रताड़ित महिलाओं की मदद करेंगी।

लावारिस लाशों का कद्रदान



2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अयोध्या के **मुहम्मद शरीफ** पिछले 25 साल में 25 हजार से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इस बुजुर्ग समाजसेवी को अयोध्या और आसपास लावारिस लाशों के कद्रदान के तौर पर जाना जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपना इलाज भी ठीक से करा सकें। बेटा गाड़ी चला कर परिवार को पालता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से परिवार काफी परेशान है। कुछ समय पहले तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। परिवार के पास बस इतने ही पैसे बचे थे कि वह उनका इलाज करा सके। मुहम्मद शरीफ साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते हैं। छोटे बेटे की मृत्यु के बाद वे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में इस तरह खो गए कि उनकी दुकान लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई। गृहस्थी की गाड़ी भी डगमग हो चली। तीन बेटे हैं। एक ने साइकिल मरम्मत की दुकान खोली। दूसरे ने मोटरसाइकिलों की मरम्मत करने का काम शुरू किया। तीसरा बेटा ड्राइवर का काम करने लगा। इतना इंतजाम हो गया कि दो वक्त की रोटी और रहने के लिए अति सामान्य सी व्यवस्था बन गई। इस बीच मुहम्मद शरीफ अपने घरेलू जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर समाज सेवा के काम में जुट गए और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराते रहे।

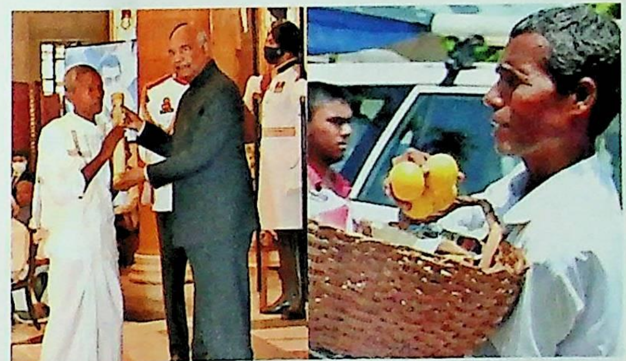
किसको दिए जाते पद्म सम्मान?

पद्म विभूषण : यह सम्मान असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।

पद्म भूषण : यह सम्मान उच्च-क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।

पद्मश्री : प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान चौथा उच्चतम नागरिक सम्मान है।

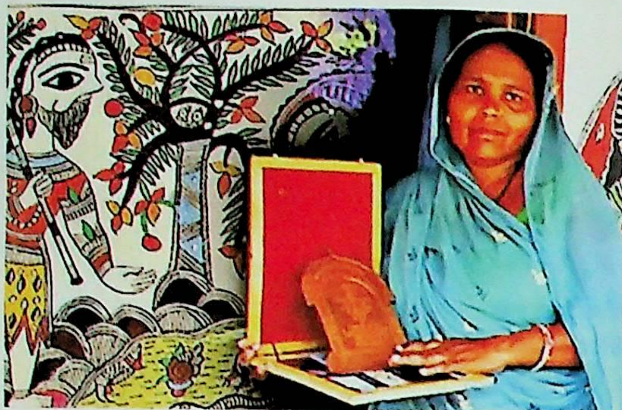
खुद निरक्षर पर संकल्प दूसरों को शिक्षित करने का



कर्नाटक में फल बेच कर शिक्षा की अलख जगाने वाले **हरे काला हजाब्बा** को कुछ समय पहले तक हम में से शायद ही कोई जानता था। बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं। बेहद मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया है, जो उन्हें असाधारण लोगों की पंक्ति में खड़ा करता है और राष्ट्र के वास्तविक नायकों में शामिल करता है। उन्हें 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसे कबीर कहते हैं कि 'मसि कागद छुओ नहीं'- इसके बावजूद वे इतने बड़े समाज सुधारक और ज्ञानी बने। हरे काला भी स्कूल नहीं गए। कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं। बिल्कुल निरक्षर। फिर भी शिक्षा की अहमियत को पहचाना। उनके भीतर यह जुनून जागा कि वे भले नहीं पढ़ पाए लेकिन ऐसा कुछ करें कि दूसरे लोग- जो अभाव के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं- शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनकी खुद की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। इस पर भी उन्होंने

अपनी कुल जमा पूंजी से बेंगलुरू में अपने गांव के पास एक स्कूल खोला। सन् 2000 से उनके गांव में यह स्कूल चल रहा है। उन्हें उम्मीद तक नहीं रही होगी कि कभी देश उनके कार्य को जानेगा-समझेगा और सम्मानित करेगा।

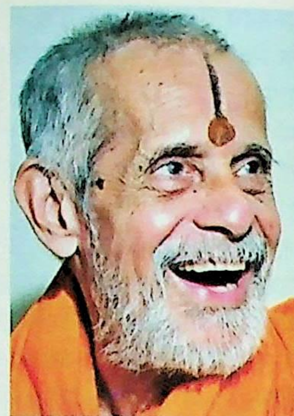
कभी थी हाथों में झाड़ू...अब जादू



दुलारी देवी को 2021 का पद्मश्री सम्मान मिला है। बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली हैं। एक बेहद गरीब मल्लाह परिवार में अभावों और गरीबी के बीच जन्म हुआ। 12 साल की हुई तो माता-पिता ने शादी कर दी। कुछ ऐसा हुआ कि 7 साल बाद ही ससुराल से मायके आ गईं। उनकी 6 महीने की बेटी नहीं रही थी। उसका काम अलग से था। पढ़ी-लिखी भी नहीं थीं कि कोई सामान्य-सा रोजगार या नौकरी कर भरण-पोषण कर पातीं। लेकिन एक जिजीविषा थी। उनके संघर्ष की दास्तान ऐसी है कि पुरुष तक हार मान जाएं। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दुलारी देवी की उम्र इस समय 54 साल है। ससुराल से मायके आकर जिंदगी की गाड़ी तो किसी तरह आगे चलानी ही थी। उन्होंने जीवन के लिए संघर्ष शुरू किया। कुछ घरों में झाड़ू-पोंछा लगाने का काम मिल गया जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। लेकिन किस्मत किसी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, यह कोई नहीं जानता। अचानक दुलारी ने हाथ में पोंछे की जगह कूंची पकड़ ली। हाथों में कमाल का जादू। भले वे लिख-पढ़ नहीं पाती थीं लेकिन चित्र गजब के बनाती थीं। मधुबनी की यह बेटी संघर्षों की जीती जागती गाथा है। दुलारी अब 'पद्मश्री दुलारी' हैं। वे सात हजार से ज्यादा मिथिला पेंटिंग बना चुकी हैं।

सेवा को समर्पित जीवन

समाज में सद्भाव और शैक्षणिक जागृति हेतु समर्पित उडुपी के पेजावर मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी **श्री विश्वेश तीर्थ** जी को मरणोपरांत 2021 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उडुपी के पेजावर मठ की गुरु परंपरा के 33वें गुरु श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी का जन्म 27 अप्रैल, 1931 को पुट्टर के रामाकुंज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1938 में 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास धारण किया था। स्वामी जी ने कई शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की। पूरे देश में उन्होंने कई ऐसे धर्मस्थलों और मठों का निर्माण किया जो तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हैं। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर गोरक्षा जैसे मुद्दों का उन्होंने भरपूर समर्थन किया।



बचपन से ही लगी थी लगन



छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक **मदन चौहान** को 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मदन चौहान का जन्म देश के स्वतंत्र होने के 2 महीने बाद 15 अक्तूबर, 1947 को हुआ। संगीत से उनका लगाव बचपन से ही था। उन्होंने खुद बताया कि जब वे केवल 10 साल के थे, तभी से वे कुछ बजाना चाहते थे। जब और कुछ नहीं मिलता था तो तब वे घर में टीन का डिब्बा बजाते थे। धीरे-धीरे उनमें संगीत का शौक जागता गया। उन्होंने कठिन साधना की और पिछले 55 साल से तबले और हारमोनियम के साथ मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं। उनके सूफी गायक बनने के संकेत संभवतः बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। बचपन से ही साधु-संतों के भजन गाना उन्हें बहुत प्रिय था। पंडित कन्हैयालाल भट्ट उनके संगीत के प्रारंभिक गुरु थे।

मुश्किलों के पहाड़ झेले पर टूटी नहीं



कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कल्लू कम्बा में जन्मी ट्रांसजेंडर **मंझम्मा जोगाठी** को 2021 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में वे सम्मान लेने जैसे ही राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास पहुंची, वहां उन्होंने नजर उतारने की रस्म अदा की। इसका पूरे हाल में तालियों से स्वागत किया गया। लोक नृत्यांगना मंझम्मा का कहना है कि ट्रांसजेंडर होने के नाते अपनी पहचान बनाने में उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने कई कलाओं में महारत हासिल की। अपने को मजबूत बनाया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की। उनका असली नाम मंजूनाथ शेट्टी है। वे कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं।

जंगलों की 'इनसाइक्लोपीडिया'



कर्नाटक की 72 वर्षीया **तुलसी गौड़ा** को पर्यावरण में अहम योगदान देने के लिए 2021 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान लेने वे अपने पारंपरिक परिधान और नंगे पैर पहुंची थीं। इस दौरान जब उनका सामना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुआ तो दोनों हस्तियों ने उन्हें नमस्कार किया। छह दशक से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल तुलसी अब तक करीब 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी हैं। हलक्की जनजाति में जन्मी तुलसी को घर में बेहद गरीबी के कारण औपचारिक शिक्षा तक नसीब नहीं हो सकी। उन्हें बचपन से ही पेड़-पौधों से काफी लगाव था। वे ज्यादा समय जंगलों में ही बिताती थीं। धीरे-धीरे पेड़-पौधों और जड़ी-बूटियों की विविध प्रजातियों की जानकारी हो गई। उसी ज्ञान के कारण आज उन्हें 'जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया' के रूप में जाना जाता है। 12 साल की उम्र से उन्होंने हजारों पेड़ लगाए और अपना उनका ख्याल रखते हुए उन्हें बड़ा किया। वे वही काम अब भी जारी रखे हैं।

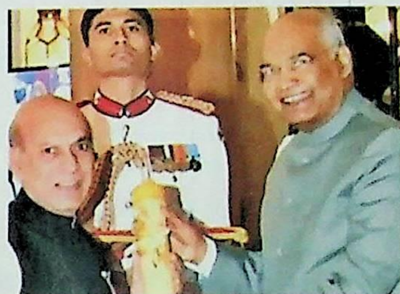
'संस्कृत' के साधक



संस्कृत के प्रकांड विद्वान और काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष **आचार्य रामयत्न शुक्ल** को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मान किया गया है। इस समय उनकी आयु 89 वर्ष है और वे अभी भी नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए काम में संलग्न हैं। वे युवाओं को संस्कृत और वैदिक विज्ञान की शिक्षा मुफ्त में देते हैं। आचार्य रामयत्न शुक्ल ने अष्टाध्याय की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करवाई है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वे संस्कृत के लुप्त होते जा रहे ज्ञान को नई पीढ़ी तक सहज रूप में पहुंचा रहे हैं। 1932 में जन्मे शुक्ल की बचपन से ही संस्कृत में बहुत रुचि थी। उन्होंने स्वामी करपात्री जी महाराज और स्वामी चेतन भारती से वेदांत शास्त्र व पंडित प्रवर हरिराम शुक्ल से मीमांसा शास्त्र और पंडित राम चंद्र शास्त्री से दर्शनशास्त्र योग की शिक्षा ली थी।

काम को मिला मान





भारत में पूर्व उच्चायुक्त **मुअज्जम अली** और 1971 युद्ध के नायक **कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर** पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक हैं। मुअज्जम अली को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष के साथ-साथ शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी मना रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ भारत ने 3 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला था। इस युद्ध में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना।



माफिया का नहीं, बल्कि सूबे में अब कानून का राज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि सूबे में अब माफिया का नहीं, हीं बल्कि कानून का राज स्थापित हो रहा है। इस बात की तस्दीक अब लोग भी खुद करते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ और आगरा जोन में हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में पहली बार पेशेवर माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया और अन्य माफिया को चिह्नित कर कार्यवाही की गई है।

प्रदेश में दशकों से माफिया और अपराधी हावी थे। जिस कारण कारोबारियों में माफिया और अपराधियों का खौफ था और कारोबारियों को दूसरे प्रदेशों में मजबूरन पलायन करना पड़ता था। सीएम योगी के माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से पुलिस एक्शन में आई और चुन-चुन कर कार्यवाही शुरू हुई। प्रदेश में 11 नवंबर तक पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ 89 सौ कार्यवाही की है, इसमें 19,203 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 3523 अपराधी घायल हुए हैं। जबकि 155 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। इसमें 1211 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। जबकि 13 शहीद हुए हैं।

एनसीआर और वेस्ट यूपी की बात करें, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मेरठ और आगरा जोन में माफिया और अपराधियों पर कार्यवाही हुई है। मेरठ जोन में 2917 एनकाउंटर में 5440 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 1588 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और 61 अपराधियों की मौत हुई है। जबकि 442 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और एक पुलिस कर्मी भी शहीद हुआ है। इसी तरह आगरा जोन में 1925 एनकाउंटर में 4980 अपराधी गिरफ्तार और 225 घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 19 अपराध ढेर भी हुए हैं। जबकि 80 पुलिस कर्मी घायल और दो शहीद हुए हैं।

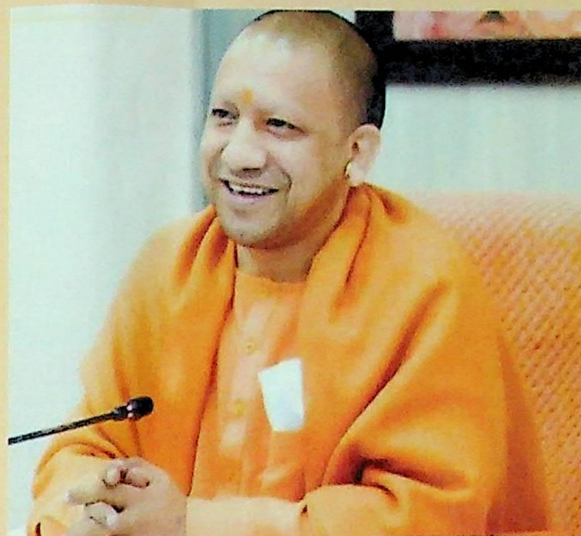
पहली बार 33 सौ माफिया को चिह्नित कर हुई कार्यवाह

पुलिस ने इस साल जुलाई माह तक प्रदेश में पेशेवर माफिया,

उत्तर प्रदेश ने कोविड पर किया प्रभावी नियंत्रण

उत्तर प्रदेश में 'ट्रेस,टेस्ट,ट्री ट' की कारगर रणनीति के परिणामस्वरूप प्रदेश में कोरोना पर सफल एवं प्रभावी नियंत्रण हो गया है। जनसंख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य के 42 जिलों में आज एक भी संक्रमित नहीं कोरोना केस नही है जबकि 17 जिलों में 01-01 मरीज ही शेष हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 73 हजार 204 सैम्पल की जांच में 69 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। केवल 06 जिलों में कुल 11 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 09 संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए।

उत्तर प्रदेश में रविवार तक कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 85 है, जबकि 16 लाख 87 हजार 216 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 9.91 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि 3.38 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की दोनो डोज देकर कोविड सुरक्षा कवर प्रदान किया जा चुका है। इस क्रम में टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 67 फीसदी से अधिक लोगों ने पहली डोज प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री के निदेर्शानसार प्रदेश में कार्यरत 73000 से अधिक



निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया गया है जिससे कोरोना की किसी भी आशंका को जड़ से नियंत्रण कर लिया जाए।

भूमाफिया, खनन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया और अन्य माफिया को चिह्नित कर कार्यवाही की। इसमें बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी के भी माफिया हैं। प्रदेश में ऐसे 3371 माफिया पर 19,121 मुकदमे दर्ज कर 2281 को गिरफ्तार किया गया और कुल 3028 आरोपियों पर कार्यवाही हुई। 42 आरोपियों के खिलाफ रासुका, 1530 पर गैंगेस्टर, 67 आरोपियों की कुर्की की गई। इसके अलावा 1030 आरोपियों पर गुंडा एक्ट, 44 आरोपियों के शस्त्र निरस्त किए गए और 911 की हिस्ट्री शीट खोली गई।

सिर्फ कार्यवाही नहीं, हीं सजा भी करा रही सरकार

पुलिस चिह्नित माफिया के खिलाफ दर्ज मुकदमो में तेजी से न सिर्फ कार्यवाही कर रही है, बल्कि सरकार की ओर से तगड़ी पैरवी भी की जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इसी कड़ी में कोर्ट ने माफिया आकाश जाट को दो मुकदमो में अलग-अलग तीन और सात साल की सजा सुनाई है। जबकि उसके गैंग के सहयोगी अमित भूरा को भी दोनों मुकदमो में तीन साल और एक साल की सजा दी गई है। चिह्नित सभी बड़े माफिया इस समय जेल में बंद हैं।

25 बड़े माफिया में 13 से ज्यादा वेस्ट यूपी के

शासन स्तर पर चिह्नित 25 बड़े माफिया में 13 से ज्यादा वेस्ट यूपी के ही हैं। इनमें गाजीपुर जिले के युसूफपुर मोहम्दाबाद निवासी मुख्तार अंसारी, प्रयागराज जिले के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र निवासी अतीक अहमद, वाराणसी जिले के चौबेपुर निवासी बृजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ जिले के हसनगंज निवासी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव, बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी मुनीर, अंबेडकरनगर जिले के हंसवार थानाक्षेत्र निवासी खान मुबारक, गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी अमित कसाना, शामली जिले के आदर्श मंडी निवासी आकाश जाट, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी उधम सिंह, मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी योगेश भदौड़ा, बागपत जिले के बड़ौत निवासी अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुर निवासी सुशील उर्फ मूंछ, मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली निवासी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी सुन्दर भाटी उर्फ नेताजी, गौतमबुद्धनगर जिले के कासना निवासी अनिल भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के बादलपुर निवासी अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर निवासी सिंघराज भाटी, गौतमबुद्धनगर जिले के जारचा निवासी अंकित गुर्जर, वाराणसी जिले के कोतवाली निवासी सुभाष सिंह ठाकुर, आजमगढ़ जिले के जीयनपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद उमेश राय उर्फ गौरा राय, गाजीपुर जिले के सैदपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सलीम, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. सोहराब और लखनऊ जिले के कैंट निवासी मो. रुस्तम हैं।



यूपी की जनता के लिए ऐतिहासिक साबित होगा ये नवंबर

उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये नवंबर ऐतिहासिक माह साबित होगा। इस महीने सूबे की जनता को कई ऐसी मेगा परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वह वर्षो -वर्ष सूबे करेंगे। ये वह मेगा परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद शुरू कराया था। इन मेगा परियोजनाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस महीने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मेगा परियोजनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सूबे की जनता को सौंपेंसौं गे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और गंगा एक्सप्रेस वे जैसी मेगा परियोजनाओं की आधारशीला भी रखेंगे। इसके अलावा गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स भी अगले माह तक शुरू हो जाएगा।

राज्य में यह पहला अवसर है जब किसी नवंबर और दिसंबर में जनता के उपयोग वाली करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार कराई गई कई मेगा परियोजनाएं जनता को सौपी सौं जाएंगी। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में करीब 42 हजार करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराया गया 340.82 किमी लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सौंपेंसौं गे। जबकि करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले माह रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्री म प्रोजेक्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास जुलाई 2018 में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस एक्सप्रेस-वे को पूर्वी यूपी के लिए लाइफ लाइन कहा जा रहा है। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक 340.824 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के फरार्टा भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, वहीं व्यापार और वाणिज्य को पंख लगेंगे। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 296.07 किमी लंबा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास बीते वर्ष 29 फरवरी को किया था। चित्रकूट से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेस वे बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन होते हुए इटावा के कुदरौल गांव के पास लखनऊ -आगरा एक्सप्रेस से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे के बनने से बुंदेलखंड पहुंचना आसान होगा, वहां कृषि, वाणिज्यिक, पर्यटन और उद्यमिता के लिए राह आसान होगी और बुंदेलखंड का विकास होगा।

इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां वह रानी लक्ष्मी बाई की 193 वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। झांसी किला परिसर में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी है। प्रधानमंत्री झांसी में नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी नोड में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा झांसी नोड में लगाई जा रही फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीडीएल झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली निर्माण की सुविधा की स्थापना करेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 183

कानपुर में विकास और सुविधाओं के नए युग की शुरूआत करेंगे सीएम

कानपुर में विकास और सुविधाओं के नए युग की शुरूआत होने जा रही है। मुख्योमंत्री योगी आदित्यलनाथ बुधवार को कानपुर मेट्रो के ट्रा यल रन को हरी झंडी दिखाएंगे । इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो में सफर कर सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यामंत्री मेट्रो कोच में उपलब्ध सुविधाओं के साथ ही प्लेटफार्मों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करेंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की शुरूआत 15 नवंबर 2019 को मुख्यरमंत्री योगी आदित्यमनाथ ने की थी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना दो साल से भी कम समय में बन कर तैयार हुई है। जो कि एक रिकार्ड है। बुधवार को 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिक सेक्स न पर ट्रायल रन की शुरुआत होगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरूआत कोविड-19 की दो लहरों के बावजूद दो साल से भी कम समय में हो रही है।

कानपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत लगभग 32.5 किमी लंबे दो मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। पहला आईआईटी से नौबस्ता जो कि 23.8 किमी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक 8.6 किमी लंबा कारीडोर है। पहले कॉरिडोर के अंतर्गत आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक पहला सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। इस सेक्शन में कुल 9 मेट्रो स्टेशन बने हैं।

कई मायनों मे देश में सबसे खास है कानपुर की मेट

कानपुर मेट्रो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से लैस होगी। इसके जरिये लगभग 35 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत होगी। यानी अगर ट्रेन ऑपरेशन में 1000 यूनिट बिजली खर्च हो रही है तो



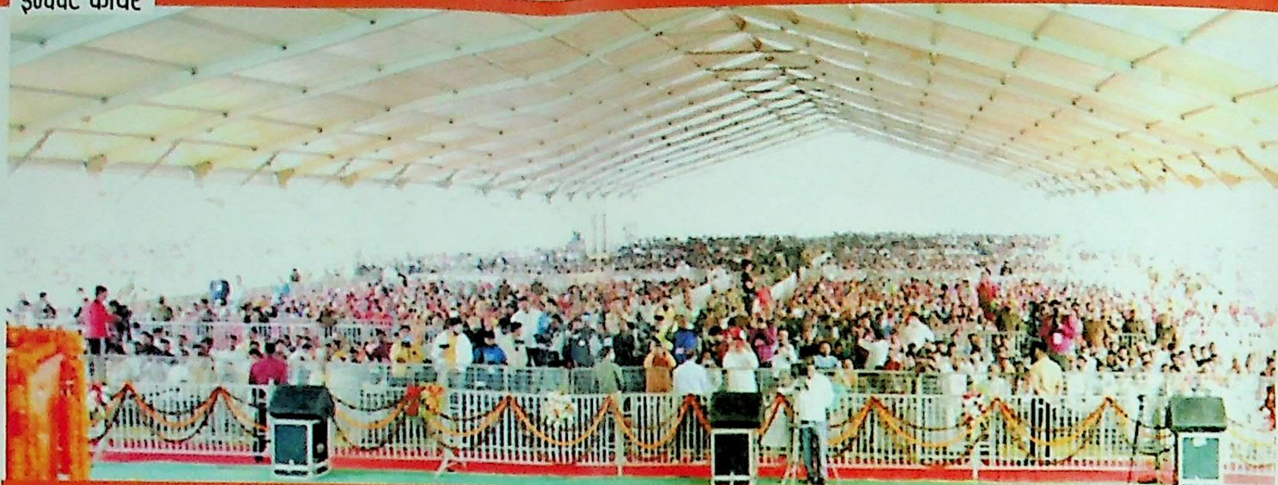
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से ट्रेनें लगभग 350 यूनिट फिर से पैदा कर लेंगी। जिन्हें वापस सिस्टम में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

स्टेशन और डिपो में लगने वाली लिफ्ट्स भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से ऊर्जा बचाने में सक्षम होंगी हों। इनमें 37 प्रतिशत तक ऊर्जा दक्षता होगी। मेट्रो के सभी परिसरों में ऊर्जा की बचत के लिए 100 प्रतिशत एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। मेट्रो डिपो और स्टेशनों पर सोलर पैनल्स लगाने की भी योजना तैयार कर ली गई है। भारत में पहली बार कानपुर मेट्रो थर्ड रेल डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के साथ होगी। खास इन्वर्टर, जो ट्रेन में लगने वाले ब्रेक्स से पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस सिस्टम में इस्तेमाल के योग्य बनाएगा। अभी तक देश में थर्ड रेल डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के साथ परिचालित किसी भी मेट्रो रेल परियोजना में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन को पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO14001 एवं संरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001 प्रमाणपत्र मिल चुके हैं ।

हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, 400 करोड़ रुपए का निवेश कर इस भूमि पर आकाश मिसाइल में उपयोग की जाने वाली प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसी परियोजना की सौगात जनता को देंगे। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो गया। इस माह के अंत तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्री म प्रोजेक्ट है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहे इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अगले माह पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी दिन जनता को सौपेंगे।

इसके साथ ही प्रधान मंत्री गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। करीब 36 हजार करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह एक्सप्रेस वे 595 किमी लंबा होगा। मेरठ से शुरू होकर यह एक्सप्रेस वे प्रयागराज पर समाप्त होगा। दिसंबर में प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे।

इसी प्रकार गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री इसी माह रखेंगे। उक्त दोनों परियोजनाएं भविष्य में सूबे की शान साबित होंगी हों औत इन दोनों परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नवंबर तथा दिसंबर में सूबे को मिलने वाली उक्त परियोजनाओं के पहले प्रधानमंत्री पिछले महीने वाराणसी, कुशीनगर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। बीते माह प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थली सिद्धार्थनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नौ नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों की सौगात प्रदेश को दी थी। तब एक साथ इतने मेडिकल कालेज की सौगात पाने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य बना था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को देश में सिरमौर बनाने में जुटे सीएम योगी के प्रयास से यह संभव हुआ था। अब इसी क्रम में प्रधानमंत्री यूपी को कई सौगात देने के लिए यूपी आने को हैं। इसके तहत ही गृहमंत्री अमित शाह भी 13 नवंबर को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे।



पलायन का मुद्दा राजनैतिक नहीं, प्रदेश की आन-बान-शान का मुद्दा : योगी

मुजफ्फरनगर दंगा हो या कैराना से लोगों का पलायन। यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश की आन-बान-शान का मुद्दा रहा है। सरकार आई तो कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की व्यवस्था की गई। इसी कारण जो लोग पलायन के लिए लोगों को मजबूर करते थे वह खुद पलायन के लिए मजबूर हो गए। धमकी की बात तो दूर, ये लोग अब सड़क पर भी नहीं चल सकते। अगर किसी ने व्यापारी, नागरिक को गोली मारने और बहन-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उन्हें गोली मारकर दूसरी यात्रा पर भेज दिया जाएगा। यह हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है।

ये बातें कैराना में सोमवार को जनसभा में मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं।

कैराना में 250 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली पीएसी बटालियन का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में भी मैं शामली आया था। तब कैराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। कैराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह ने जोर-शोर से उठाया था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की सोच थी, उसी को जमीन पर उतारने के लिए हम ढेर सारी योजनाओं के साथ आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की मांग थी कि पीएसी का एक बटालियन होना चाहिए। 250 करोड़ की लागत से इस बटालियन की आधारशिला रखने के लिए यहां आया हूं। 1278 पीएसी के जवान इस बटालियन में रहेंगे। किसी भी विपरीत स्थिति को रोकने के लिए यह बटालियन काम करेगी। जब इन जवानों का डंडा चलेगा तो यहां के अपराधियों के सामने अपने गले में तख्ती लटकाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यही आश्वासन देने के लिए यहां आया हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या कैराना का पलायन। यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, हीं बल्कि प्रदेश और देश के.आन-बान-शान का मद्दा है। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे, तबभी हम कहते थे कि इस स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार आई तो कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की व्यवस्था की है। जो पलायन के लिए लोगों को मजबूर करते थे, वह खुद पलायन के लिए मजबूर हो गए। धमकी की बात तो दूर ये लोग अब सडक पर भी नहीं चल सकते। अगर किसी ने व्यापारी और नागरिक पर गोली मारने की कोशिश की तो उन्हें ही उलटे गोली मारकर दूसरी यात्रा पर भेज दिया गया। यह हमारे लिए अस्मित का मुद्दा है। किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन बहन-बेटियों की इज्जत साथ या व्यापारियों के साथ अराजक स्थिति पैदा करेगा तो उन्हें इसकी ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी।

उन्होंनेन्हों कहा कि देश की आंतरिक और वाह्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। जिन लोगों के लिए वोट सर्वोपरि है, वह मुजफ्फरनगर दंगाइयों और कैराना के आतताइयों को सम्मान करते थे, क्योंकिक्यों उन्हें इनका वोट पसंद था। जब कैराना में दो निर्दोष हिन्दू मारे गए, हिन्दुओं के घर जलाए तब उन्हें जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन यह धर्मचक्र है, समय बदलता है। मोदी जी ने यह चक्र ऐसा घुमा दिया है जो लोग पहले मंदिर में जाने से संकोच करते थे वह आज इतना बड़ा टीका लगाते हैं कि वही सबसे बड़े हिन्दू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है इसी ताकत का अहसास कराने हम आए हैं।

सीएम योगी ने उपस्थित लोगों से कहा कि मोदी जी पर आपने विश्वास किया उन्होंनेन्हों गरीब की कल्याणकारी योजनाओं को हर गांव हर परिवार तक पहुंचा दिया। विकास की बड़ी योजनाओं को भी लागू किया। उन्होंनेन्हों सबका विकास सबका विश्वास जीतने का काम किया। प्रदेश के अन्दर साढ़े चार वर्ष में सरकार कैसे चलनी चाहिए यह भी दिखा दिया। पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए सरकार चलती थी । नौकरी भी लगती थी तो चेहरा देखकर, अब तो शामली के नौजवानों का ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंनेन्हों याद दिलाया कि हमारे सांसद और विधायक के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।

जिसमें वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह और सुरेश राणा भी शामिल थे। उन्होंनेन्हों कहा उस समय दंगाइयों को घर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। विकास पर कुछ नहीं होता था। तब विकास का मतलब एक परिवार होता है। न सड़क, न समय पर खाद, न बीज, न आवास, न बिजली, न रसोई गैस और न गरीब को उपचार के लिए कोई व्यवस्था थी। मोदी जी आए तो गरीब को पक्का मकान दिया, हर गरीब को पांच लाख स्वसथ्य बीमा का कवर, निशल्क गैस कनेक्शन, फ्री बिजली कनेक्शन। 12 करोड़ गरीब किसानों को सम्मान निधि के रूप में समय से रुपया पहुंच जाता है, लेकिन विपक्षियों के पास इनके लिए कोई योजना नहीं थी।

उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जब नौकरी की बात आती थी तो पूरा खानदार वसूली पर निकल पड़ता था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 425 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें पालीटेक्निक, अस्पताल, पेयजल योजनाएं शामिल हैं। उन्होंनेन्हों कहा कि शामली बिजली के लिए तरसता था। हमने 800 करोड़ की लागत का बिजली स्टेशन शामली को दे दिया है। उपचार के लिए मेडिकल कालेज स्थापति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार ने कोरोना काल में इलाज की इतनी अच्छी व्यवस्था की कि दिल्ली के लोग उपचार के लिए यहां आना पड़ा।

संगीत का बेहतरीन घराना होने के कारण फिल्मी जगत के लिए कैराना महत्वपूर्ण था लेकिन कुछ लोगों ने अपनी नफरत और फितरत के कारण कैराना को बदनाम किया। यहां जो जन व धन हानि हुई है। इस मामले में कुछ पर कार्रवाई हुई है। जो बचे हैं उन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित हैं, उन्हें मुआवजा व अन्य सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। जो व्यापारी पलायन कर गए थे आज वह वापस आए हैं। व्यापार में निवेश करके जो कारोबार को बढ़ा रहे हैं उन्हें मैं अभिनंदन किया है।

उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में 370 समाप्त हो गई। तीन तलाक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब तो अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। जो लोग भव्य मंदिर नहीं चाहते थे। जो 370 का विरोध करते थे वे लोग तब खुश होते हैं जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है कैराना में पलायन होता है या अफगानिस्तान में तालिबान शासन होता है, लेकिन हम यह नहीं होने देंगे। यह बहन-बेटियों के जीवन को नारकीय बनाता है। देश में जो कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश जब शांति और विकास के रास्ते पर बढ़ा है। यह केवल राष्ट्रधर्म की सोच के कारण संभव हुआ है। शासन की सुविधाओं के साथ-साथ हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जाम की समस्या का समधान के लिए सहारनपुर बाईपास बन रहा है।

सवा साल में फ्लिपकार्ट पर बिके रु. 1,000 करोड़ के 02 करोड़ ओडीओपी उत्पाद

Flipkart



उत्तर प्रदेश के परंपरागत शिल्प को प्रोत्साहन देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव योजना 'एक जनपद-एक उत्पाद' के शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट पर बीते सवा साल में रु.1,000 करोड़ के 02 करोड़ से अधिक ओडीओपी उत्पाद खरीदे गए हैं। सोमवार को फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी से भेंट कर उन्हें यह जानकारी दी, साथ ही ओडीओपी योजना के लिए सीएम का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस भेंट में फ्लिपकार्ट के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने सीएम योगी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनके पोर्टल के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये के दो करोड़ से अधिक ओडीओपी उत्पाद बिक चुके हैं। यही नहीं, हीं बिक्री में वर्ष 2020 से अब तक हर तिमाही में पिछली तिमाही 52 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे शिल्पकारों को भी खासी आमदनी हुई है। फ्लिपकार्ट पर ओडीओपी उत्पादों को लेकर लोगों के शानदार उत्साह पर सीएम योगी ने खुशी जताई। उन्होंनेन्हों कहा कि ओडीओपी योजना ₹आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश₹ के सपने को पूरा करने का महत्वपूर्ण आधार है। आज पूरी दुनिया में हमारे पारंपरिक शिल्प उत्पाद पसंद किए जा रहे हैं। यह शिल्पियों को आर्थिक स्वावलम्बन तो दे रही है, उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान भी मिल रही है। सीएम ने कहा कि शिल्पकारों को आधुनिक उपकरण व जरूरी प्रशिक्षण सहित जिस भी चीज की जरूरत होगी, सरकार उन्हें मुहैया कराएगी।

बता दें कि पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सभी 75 जिलों के एक-एक पारंपरिक शिल्प को आधार बनाते हुए 'एक जिला एक उत्पाद योजना' की शुरूआत की। योजनांतर्गत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने संभावनाओं वाले उत्पादों को हर जिले से चुना। सरकार ने शिल्पकार और कारीगरों के कौशल विकास के साथ ही उन्हें संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया। न सिर्फ उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया, बल्कि उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए विभिन्न ई-मार्केट पोर्टल से भी करार हुआ। इस तरह प्रदेश से होने वाले कुल निर्यात में ओडीओपी की हिस्सेदारी लगभग 80 फीसद पर पहुंच गई। देखते ही देखते ओडीओपी योजना पूरे देश में छा गई। अब इस कड़ी में नई उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक मौकों पर इसकी तारीफ की तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट पेश करते समय इस योजना का जिक्र किया और इसे पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया।

लेते हो चंदा बताओ जरा धंधा



नए एफसीआरए संशोधन कानून पर देश के एनजीओ तबके में तीखी प्रतिक्रिया है। कुछ एनजीओ इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंचे परंतु अदालत ने विदेशी चंदे के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाकर सिविल सोसाइटी को बड़ा झटका दिया है न्यायालय के ताजा रुख के बाद मिशनरी एवं इस्लाम आधारित एनजीओ में खलबली मची है

■ डॉ. अजय खेमरिया

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक अहम आदेश दिया। इसके तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के खर्च पर निगरानी का रास्ता साफ होने के आसार हैं। दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय तो सुरक्षित रखा लेकिन इस दौरान जो बातें कही गईं, वे उदारवादियों की आड़ में चल रहे एनजीओवाद के लिए बड़ा झटका हैं। खासकर विदेशी चंदे से भारत की संप्रभुता और अखण्डता को चुनौती देने वाले एक बड़े तबके के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ताजा रवैया निराशाजनक ही है।

केयर एंड शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल हार्पर और जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने एफसीआरए एक्ट 2010 के संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नबम्बर को एफसीआरए एक्ट संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में यह तय करना है कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (एफसीआरए) में संशोधन कर बनाए गए नए विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम (2020) में हुए परिवर्तन संवैधानिक हैं या नहीं।

न्यायालय का कड़ा रुख

सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों ने उस धन का दुरुपयोग नहीं किया है और इसका इस्तेमाल केवल उस उद्देश्य के लिए किया है, जिन उद्देश्यों के लिए फंड लिया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आप (केंद्र सरकार) इसे पहले सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, तो इसे अभी से सुनिश्चित कर लें। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की बेंच ने मामले में सुनवाई

2010 से 2019 की अवधि में विदेशी चंदे की वार्षिक आमद दोगुनी हुई

2016-17 और 2018-19में विदेशों से 58 हजार करोड़ रुपये भारतीय एनजीओ को मिले

12 एनजीओ रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने के आरोप में चिह्नित



पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग नहीं किया जाए,अन्यथा एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) का उद्देश्य हल नहीं होगा। इसपर केंद्र सरकार ने दलील पेश करते हुए कहा कि अगर विदेशी योगदान अनियंत्रित हुआ तो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विदेशी फंड को विनियमित करने की जरूरत है, वरना नक्सली गतिविधि या देश को अस्थिर करने के लिए पैसा आ सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से न्यायालय में यह भी बताया गया है कि विकास कार्यों के लिए आने वाले पैसे का इस्तेमाल नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है।

विदेशी चंदे से षड्यंत्रकारी गतिविधियां

पिछले साल से लागू नए एफसीआरए संशोधन कानून को लेकर देश की सिविल सोसाइटी में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। असल में नया विदेशी अभिदाय कानून (एफसीआरए)भारत की धरती पर भारत के ही कुछ नागरिक समूहों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को निषिद्ध करने का विधिक प्रावधान स्थापित करता है। सच्चाई यह है कि मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, कुपोषण और नागरिक अधिकारों के नाम पर भारत में विदेशी षड्यंत्र लंबे समय से फल-फूल रहे हैं। मामला चाहे नक्सलियों के समर्थन का हो या परमाणु और कोयले से जुड़ी विकास परियोजनाएं, कुछ एनजीओ ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अवरुद्ध करने का काम ही किया है। यूपीए सरकार के दौर में अमेरिका से परमाणु ऊर्जा समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस एनजीओवाद पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खेहर ने भी प्रशांत भूषण को इसी भावना के साथ कड़ी फटकार लगाई थी। सिविल सोसाइटी की आड़ में प्रतिक्रियावादी तत्वों की भूमिका को आज राष्ट्रीय सन्दर्भ में गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए गए नए कानून के बाद अब सभी गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा प्राप्त करने के क्रम में अपने सभी पदाधिकारियों के आधार नंबर दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट कराने होंगे। इस मद में मिलने वाली रकम एसबीआई के एक विशिष्ट खाते में जमाकर इसका व्यय प्रतिवेदन भी सरकार को सौंपना होगा। अभी सरकार के समक्ष ऐसे तमाम प्रकरण आए हैं जिनमें विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग मद परिवर्तित कर सरकार और विकास परियोजनाओं के विरुद्ध लोगों को भड़काने में किया गया है। 2010 से 2019 की अवधि में विदेशी चंदे की वार्षिक आमद दुगुनी हुई है। खास बात यह है कि 2016-17 और 2018-19 में विदेशों से 58 हजार करोड़ रुपये भारतीय एनजीओ के खातों में आए हैं। अकेले अमेरिका से यह आंकड़ा तीन खरब और फ्रांस से तीन अरब रुपये वार्षिक है। यह राशि भारत सरकार के कुछ कल्याणकरी विभागों के बजट से अधिक है। देश में करीब 22,500 ऐसे संगठन हैं जो इस धनराशि को अपने कार्यक्रमों के नाम पर अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, यूरोप से लेकर इस्लामिक देशों से प्राप्त करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेपरेरी स्टडीज को चीन से प्राप्त लाखों डॉलर के व्यय की जांच पिछले साल ईडी को सौंपी गई है।अध्ययन के नाम पर इस थिंक टैंक ने यूरोपीय आयोग, आयरलैंड सरकार और सयुंक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे संगठनों से भी बड़ा चंदा हासिल किया।

हाल ही में गृह मंत्रालय ने 12 एनजीओ को चिन्हित किया था जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने,उन्हें

22,500 एनजीओ अमेरिका,चीन,जापान, कनाडा, यूरोपसे लेकर इस्लामिक देशों से प्राप्त करते हैं फंड

3 प्रतिशत जीडीपी का घाटा भारत को एनजीओ प्रेरित कानूनी अड़ंगों,धरना-प्रदर्शन के चलते होता है

20,673 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद किए गए हैं अब तक

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने उस धन का दुरुपयोग नहीं किया है और इसका इस्तेमाल केवल उस उद्देश्य के लिए किया है, जिन उद्देश्यों के लिए फंड लिया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आप (केंद्र सरकार) इसे पहले सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, तो इसे अभी से सुनिश्चित कर लें

सयुंक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रावधानों के अनुरूप कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। इन संगठनों में एमेनेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय पदाधिकारियों के अलावा कोलकाता का 'बोन्दी मुक्ति संगठन' शामिल था। रोहिंग्या के मामले में सक्रिय अधिकतर एनजीओ दिल्ली में समाजकर्म के नाम पर पंजीकृत हैं। इस एनजीओ से जामिया के एक प्रोफेसर के साथ भारतीय विदेश सेवा के एक पूर्व अधिकारी भी जुड़े हैं। मुख्य धारा के मीडिया से बाहर हुए बड़े पत्रकारों एवं विवि शिक्षकों का एक सुगठित तंत्र देश में काम कर रहा है। अल्पसंख्यक, मानवाधिकार हनन, आदिवासी, कश्मीर, पूर्वोतर मुद्दों पर अध्ययन के नाम पर भारत को बदनाम करना इस तंत्र का मुख्य व्यवसाय बन गया है। जकात, सबरंग, सफदर हाशमी ट्रस्ट, सद्भावना, कंपैशन इंटरनेशनल, यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, पीएफआई, नव सर्जन ट्रस्ट, पीपुल्स वॉच, अनहद जैसे तमाम संगठनों पर धर्मांतरण और समाज तोड़ने के कुत्सित एजेंडे पर काम करने के आरोप हैं। अधिकांश बड़े एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आश्रय के नाम से छोटे एनजीओ को यह राशि हस्तांतरित कर देते हैं। मदर एनजीओ मैदानी संगठनों के जरिए ही अपना एजेंडा पूरा कराते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के संगठन को फंड दुरुपयोग कर साम्प्रदायिक दुष्प्रचार का दोषी पाया गया है। नवसृजन ट्रस्ट भी गुजरात में दलितों को भड़काने में अग्रणी है।

मनीष सिसौदिया के एनजीओ 'कबीर' को फोर्ड फाउंडेशन से 1.97 लाख डॉलर की मदद मिली थी। अरुंधति राय खुद इसके दुरुपयोग का आरोप लगा चुकी हैं। 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार में भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रही इंदिरा जयसिंह के एनजीओ 'लायर्स कलेक्टिव' पर भी विदेशी मदद के दुरुपयोग का संगीन आरोप विचाराधीन है। इस संस्था को 2006 से 2014 के मध्य एफसीआरए से 33.39 करोड़ की मदद मिली। उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, ओपेन सोसाइटी के अलावा लाबीस्ट्रॉस से धन हासिल किया था। ग्रीन पीस और फोर्ड फाउंडेशन समेत अनेक मिशनरीज और जिहादी उद्देश्यों वाले एनजीओ भारत में न केवल गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठा रहे हैं बल्कि भारतीय शासन और राजनीति को भी सीधे प्रभावित कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर किसान आंदोलन तक देश भर में माहौल को विषाक्त करने में इसी चिन्हित वर्ग की भूमिका सन्देह के दायरे में है।

आईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु बिजलीघर, कोयला बिजलीघर, यूरेनियम खदान, जीएम तकनीकी, पनबिजली परियोजना के मामलों में पहले अध्ययन के नाम पर मिथ्या रिपोर्ट प्रचारित की जाती है। फिर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनजीओ प्रेरित कानूनी अड़ंगों, धरना-प्रदर्शन के चलते भारत को 3 प्रतिशत जीडीपी का घाटा उठाना पड़ता है।

मोदी सरकार की कार्रवाई

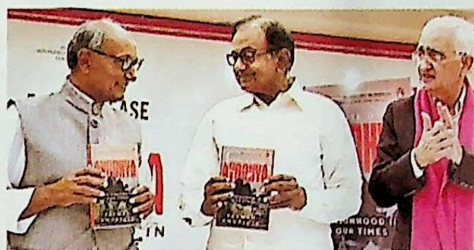
मोदी सरकार ने 2014 से इन संस्थाओं की संदिग्ध गतिविधियों को खंगालने की कार्रवाई आरम्भ की और अभी तक 20,673 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं। देश मे 33 लाख एनजीओ में से केवल 10 प्रतिशत ही सरकार को नियमित रिपोर्ट करते हैं। खुद पी. चिदम्बरम ने गृह मंत्री के रूप में संसद में स्वीकार किया था कि आधे से अधिक एफसीआरए प्राप्त संगठन न केवल धन का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि सरकार को कोई रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। नोएल हार्पर और जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिकाओं में एफसीआरए संशोधनों को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि संशोधन ने विदेशी धन के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों पर कठोर और अत्यधिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्नीस हजार से अधिक एनजीओ नए कानून के तहत विदेशी धन के लिए नई दिल्ली की एसबीआई शाखा में अपना खाता खोल चुके हैं। उदारवादियों की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले एक बड़े वर्ग में अभी भी इस कानून को लेकर खलबली है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा रुख के बाद मिशनरी एवं इस्लाम आधारित एनजीओ का परेशान होना स्वाभाविक ही है। ■

उसका दाग, इसके माथे

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद दिग्विजय सिंह और पी. चिदंबरम ने भी उगला जहर

■ पाञ्चजन्य ब्यूरो

कांग्रेस ने एक बार फिर हिंदुत्व के विरुद्ध जहर उगला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' में हिंदुत्व की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद ने लिखा है कि हिंदुत्व का राजनीतिक रूप मौजूदा दौर में साधु-संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म से अलग कर रहा है, जो हर तरह से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। खुर्शीद ने यह टिप्पणी 'द सैफ्रन स्काई' शीर्षक वाले अध्याय में की है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन मुगलों के 500 साल और 150 साल के ईसाई शासन में जब हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा तो अब उसे किस बात का खतरा है। वहीं, पी. चिदंबरम ने कहा कि 6 दिसंबर, 1992 को जो कुछ भी हुआ, वह बहुत गलत था। विवादित ढांचा ध्वंस में करीब 300 आरोपी थे, जो बरी हो गए। जैसे किसी ने जेसिका को नहीं मारा, वैसे ही किसी ने विवादित ढांचा भी ध्वस्त नहीं किया।



पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद के साथ दिग्विजय सिंह और पी. चिदंबरम

इस मामले में भाजपा ने खुर्शीद, दिग्विजय और कांग्रेस पार्टी सहित इसके शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथ लिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह केवल खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यही कांग्रेस की असलियत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार-बार ऐसा होता है। चुनाव के दौरान इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में क्या यह कहने का साहस करेंगे कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस और बोको हरम की विचारधारा है। संयुक्त राष्ट्र ने जिस आईएसआईएस और बोको हरम को आतंकी संगठन माना है, उनसे आप 100 करोड़ हिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्ण सहिष्णु होने का प्रमाण दिया। भाटिया ने सोनिया गांधी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपके निशाने पर कोई और नहीं, बल्कि देश की आन-बान-शान हिंदू समाज है। भाटिया ने इसे भारत की पंथनिरपेक्षता का अपमान बताते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यह तक कहा गया कि प्रभु श्रीराम काल्पनिक हैं।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अगर वे भारत की परंपरा से परिचित होते तो ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे भारत की संस्कृति को संजोने का काम करें, बांटने का नहीं, मां से प्रार्थना है कि ऐसे विचार रखने वाले लोगों को सद्‌बुद्धि दें। वहीं, भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि हम उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी पार्टी ने सिर्फ इस्लामिक जिहाद के साथ समानता लाने व मुस्लिम वोट पाने के लिए 'भगवा आतंकवाद' शब्द गढ़ा?

अयोध्या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी खुर्शीद ने टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे पर समाज में बंटवारे की स्थिति थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसका समाधान निकाला। अदालत का फैसला ऐसा है जिससे किसी को न लगे कि उनकी हार या जीत हुई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुत्व समर्थक इसे इतिहास में अपने गौरव को मान्यता मिलने के तौर पर देखेंगे। भाजपा की ओर इंगित करते हुए खुर्शीद ने कहा कि अयोध्या के उत्सव को देखकर लगता है कि यह एक ही पार्टी का उत्सव है। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के एक धड़े को इस बात का पछतावा है कि पार्टी की छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। इसलिए जब अयोध्या पर अदालत का फैसला आया तो उन्होंने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए यह घोषणा कर दी कि वहां भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत के आदेश के उस हिस्से की अनदेखी की, जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन देने की बात कही गई थी। इस बीच, दिल्ली के दो वकीलों, विवेक गर्ग व विनीत जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें सलमान खुर्शीद के खिलाफ धारा 153, 153ए, 298 और 505(2) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। ■

सनातन एकता के प्रतीक हैं तीर्थस्थल



गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर

हमारे तीर्थस्थल सामाजिक समरसता के केंद्र हैं। इन तीर्थों ने ही भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़कर रखा है। हर हिंदू की यही इच्छा रहती है कि वह जीवन में कम से कम एक बार इन तीर्थों के दर्शन करे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है

■ डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन

हाल ही में कई तीर्थस्थलों में जाना हुआ। प्रारंभ में अमरनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यह अमरनाथ यात्रा के प्रथम पूजन का अवसर था। वहां केवल पूजन में भाग लेने वाले, सुरक्षाकर्मी और व्यवस्था में लगे लोग ही थे। अतः भगवान के चरणों में पर्याप्त समय रुकने का सौभाग्य मिला। वहां बैठे हुए मैं अचानक वहां से 3,500 किलोमीटर दूर रामेश्वरम पहुंच गया और कुछ ही समय के बाद मुझे 2,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान सोमनाथ के दर्शन हुए। वहीं 1,500 किलोमीटर दूरी पर स्थित महाकाल तो मुझे सामने ही दिख रहे थे। मैं विचार कर रहा था कि आखिर वह कौन-सा तत्व है, जो एक दुर्गम स्थान पर बैठे होने पर भी इतने विशाल देश के सभी कोनों में स्थित तीर्थों के साथ जोड़ देता है। यह भाव मेरे मन में ही नहीं, भारत के सभी तीर्थयात्रियों के मन में आता होगा। यह वही एकात्म भाव है जो अनादि काल से एकसूत्र में पिरोता है और भारत को एक जीवंत राष्ट्र के रूप में संजोकर रखता है।

भारत जैसे आध्यात्मिक देश की आत्मा तीर्थों में ही निवास करती है। ये तीर्थ भारत की न केवल पहचान हैं, अपितु भारत को पारिभाषित भी करते हैं। कहा गया है- 'तरति पापादिकं यस्मात'।

यानी जिसके द्वारा मनुष्य पाप आदि से तर जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। हर भक्त तीर्थस्थान पर जाते समय अपने द्वारा किए गए हर पाप का प्रायश्चित करता है और अपने इष्टदेव से उन पापों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करता है। तीर्थ का एक और अर्थ है 'ती' का अर्थ है तीन। 'अर्थ' का मतलब है प्रयोजन। जहां तीन प्रयोजन सिद्ध हो जाएं वही तीर्थ है। चार पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) में से अर्थ के उपयोग से ही भक्त तीर्थ जाते हैं, परंतु वहां बाकी तीन पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। वह मान कर चलता है कि अब तीर्थ में आने के बाद उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रह सकती। तीर्थों का महत्व अनंत है, तीर्थों के दर्शन के लिए एक हिंदू अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता है। कई विहंगम तीर्थों जैसे मानसरोवर, अमरनाथ आदि के दर्शन के लिए तो वह कई बार अपने प्राणों के उत्सर्ग के लिए भी तैयार रहता है। तीर्थों के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं, तो वहीं कुछ कहते हैं कि वे साक्षात् भगवान् हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश, नगर और ग्राम में तीर्थ है। वेदांत के अनुसार तो इस पुण्य भूमि का कण-कण ही तीर्थ है। कुछ स्थानों के तीर्थ बनने के कुछ विशिष्ट कारण होते हैं। भारत अवतारों की धरती है। भगवान विष्णु के ही 11 अवतार हुए, जिन्होंने संपूर्ण भारत के अलग-अलग स्थानों पर अपनी लीलाएं की हैं। अकेले भगवान राम के वनगमन के 196 स्थान अंकित किए जा चुके हैं। सभी की जन्मस्थली व उनकी लीलाओं से संबंधित हजारों स्थल आज तीर्थ के रूप में प्रेरणास्थल बन चुके हैं।

ऋषि-मुनियों की तपोभूमि

भारत संत-महात्माओं और ऋषि-मुनियों का देश है। सृष्टि के निर्माण से लेकर भारत के भौतिक, आध्यात्मिक विकास का हर क्षण किसी न किसी संत की साधना व तपस्या का साक्षी है। चारों धाम (द्वारिका, बदरीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम) आदिशंकराचार्य की तपस्थली ही थे, जिनके दर्शन करके प्रत्येक हिंदू अपने जीवन को धन्य मानता है। सुदूर कश्मीर में महर्षि कश्यप से लेकर केरल में नारायण गुरु, पश्चिम में नरसी मेहता से लेकर पूर्वोत्तर में शंकरदेव आदि इन विभूतियों ने हजारों स्वनामधन्य संत भारत में हुए हैं,

वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत त्रिपिटक, आगम, गुरुग्रंथ साहिब आदि अन्य पवित्र ग्रंथों की रचना कर भारत की आध्यात्मिक धरोहर को संपन्न किया है। विश्व को अनमोल आविष्कार व विभिन्न नई वस्तुएं देने वाले वैज्ञानिक भी संत ही रहे हैं। भारत पर आने वाले संकटों से जूझने की क्षमता को निर्माण करने का कार्य भी संत ही करते रहे हैं। इन संतों की जन्मस्थली व तपोस्थली तीर्थ के रूप में आज भी उनके संदेश को भक्तों तक अविरल प्रेषित करती रहती हैं।

पवित्र नदियों व पर्वतों का सान्निध्य

हिंदू संस्कृति मूलतः प्रकृति पूजक है। सृष्टि के हर अंग में एकात्म भाव का दर्शन भरतीय संस्कृति की विशेषता है। पर्वत और नदियां तो जीवनदायी हैं। इसलिए हर प्रमुख पर्वत को देवता व नदी को देवी मानकर उनकी आराधना करना, उनकी पवित्रता को बनाए रखना हमारी संस्कृति का अनन्य भाग है। हर पर्वत पर किसी न किसी देवता का निवास या संतों की तपोस्थली का होना उन पर्वतों के कण-कण को तीर्थ बना देता है। उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में अरावली, विंध्याचल रैवतक होते हुए पूर्व में महेंद्र पर्वत और दक्षिण के मलय एवं सहयाद्रि पर्वत तीर्थ के रूप में पूज्य हैं, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र ,गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि अनेक नदियों के उद्गम स्थल से लेकर उनके प्रवाह एवं संगम स्थलों पर अनेक तीर्थों का विकास हुआ है।

किसी भी तीर्थ पर किसी की जाति-वर्ण पूछ कर प्रवेश नहीं होता। सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने इष्ट देव का उच्चारण करते हुए यात्रा करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। सब सामूहिक रूप से बिना किसी भेदभाव के स्नान, ध्यान और पूजन करते हैं। समरसता का यही भाव हिंदू संस्कृति की मूल विशेषता है। चराचर जगत में ईश्वरत्व के दर्शन करने वाला हिंदू कभी ऊंच-नीच के भाव से प्रेरित नहीं हो सकता।

शिवलिंग आदि विग्रहों का प्रकटीकरण

आदिपुरुष आशुतोष भगवान शंकर प्राणियों के कल्याण के लिए स्थान-स्थान पर वास करते हैं। जिस-जिस पुण्य क्षेत्र में भक्त जनों ने उनकी अर्चना की, उसी क्षेत्र में वे आविर्भूत हुए तथा ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से अभिहित इन तीर्थों के अपने जीवन काल में दर्शन करना प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त शक्ति स्वरूपा मां व कई अन्य देवी-देवताओं के विग्रह भारत के कई स्थानों पर स्वयंभू प्रकट हुए हैं।

सती के अंगों के पात स्थल

52 शक्तिपीठ उन सब स्थानों पर बने हैं जहां मां भगवती सती के शव के विभिन्न अंगों का पात हुआ था। इन 52 शक्तिपीठों के अलावा कुछ अन्य स्थान भी हैं जिनकी मान्यता शक्तिपीठों जैसी ही है। इन सब तीर्थों के अतिरिक्त भारत में उद्भुत कई आध्यात्मिक परंपराओं के महापुरुषों से संबंधित स्थल भी तीर्थ बन गए हैं जिनका सम्मान भारत की सभी परंपराओं के अनुयायी करते हैं। जैन मत में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन सबके जन्मस्थल, तपस्थल व निर्वाण स्थल भारत के प्रमुख तीर्थों के रूप में सम्मान पाते हैं। बौद्ध मत के प्रवर्तक भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा से संबंधित कई स्थल संपूर्ण विश्व के लिए तीर्थ बन गए हैं। सिख मत के 10 गुरुओं की जीवन यात्रा से



रामेश्वरम का प्रसिद्ध मंदिर

जुड़े तीर्थ आज संपूर्ण भारत के प्रेरक स्थल हैं। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। देश सभी परंपराओं से संबंधित तीर्थों की सूची बन ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि भारत तो कण-कण ही तीर्थ है।

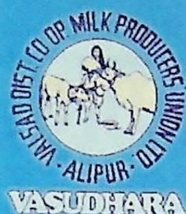
इन लाखों तीर्थों और इनसे जुड़ी यात्राओं पर करोड़ों भक्त संपूर्ण विश्व से आते हैं। अगर इन तीर्थस्थानों की दुर्गमता या अन्य बाधाओं के कारण उनको कोई कष्ट भी होता है तो वह इन कष्टों को प्रभु कृपा समझकर उनका भी आनंद लेते हैं। कुछ भक्त तो इन कष्टों को अपने कर्मों का क्षय मान कर ईश्वरत्व का अनुभव करते हैं। इन तीर्थों पर जाकर ईश्वर की महत्ता और अपनी लघुता का अनुभव होता हैं। इस आध्यात्मिक आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

इस आध्यात्मिक अनुभव के अतिरिक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा में इन तीर्थों का योगदान अतुलनीय है। इन सभी तीर्थों में एक मूल तत्व विराजमान है। सभी तीर्थस्थलों का विचार करते ही हमारे सामने सांस्कृतिक भारत का चित्र आ जाता है। ये तीर्थ ही भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं तो राष्ट्रीय एकात्मता का मंत्र भी इन तीर्थों के पीछे दिखाई देता है। विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र होने के कारण भारत ने अनेक झंझावातों को झेला है। इन सब के बावजूद आज भी भारत एक है तो उसके पीछे राजनीतिक सत्ता नहीं, ये तीर्थ ही प्रमुख कारण हैं। इन तीर्थों का निर्माण करने वाले महापुरुषों, ऋषियों की महान दृष्टि और हमारी सनातन परंपरा ही भारत को एक रखती है। ये तीर्थ ही हमें राष्ट्र बनाते हैं और राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखते हैं। अपने राष्ट्र की विराटता और एकता के अद्‌भुत संगम का दर्शन इन्हीं तीर्थों के दर्शन से होता है।

हमारे तीर्थ सांप्रदायिक सद्‌भाव के अनुपम उदाहरण हैं। अधिकांश तीर्थ हमारी सांझी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, तो जैन मत के 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और भगवान बुद्ध की तपोस्थली भी है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, तो जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने भी यहीं जन्म लिया। रामेश्वरम शैव और वैष्णव दोनों के लिए समान रूप से पूज्य है, तो काशी और प्रयाग में कई संप्रदायों के श्रद्धा स्थल हैं। हमारी सभी पर्वत श्रृंखलाएं भारत के कई संतों, महापुरुषों की तपोस्थली रही हैं। इसलिए किसी पंथ के अनुयायी अगर अपने पंथ से जुड़े किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहां अन्य पंथों से जुड़ी स्मृतियों के भी दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। इसीलिए भारत में सैकड़ों आध्यात्मिक परंपराएं होने के बावजूद परस्पर सद्‌भाव रहता है और ये सभी अपने को एक-दूसरे का सहगामी मानते हैं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण कभी-कभी अलगाव का भाव निर्माण करने का प्रयास होता है परंतु अंततोगत्वा अंतर्निहित सद्‌भाव ही विद्यमान रहता है।

हमारे तीर्थ सामाजिक समरसता के अप्रतिम प्रतिबिंब हैं। इन तीर्थों, उनसे जुड़ी यात्राओं और आयोजनों में करोड़ों हिंदू भाग लेते हैं। कुंभ के आयोजन में तो लगभग 10 करोड़ आस्थावान आते ही हैं। केवल कुंभ, कावड़, पंढरपुर, सबरीमला, अमरनाथ, वैष्णो देवी, तिरुपति, शिर्डी आदि में सहभागियों की संख्या 20 करोड़ के लगभग हो जाती है। किसी भी तीर्थ पर किसी की जाति-वर्ण पूछ कर प्रवेश नहीं होता। सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपने इष्ट देव का उच्चारण करते हुए यात्रा करते हैं और जीवन को धन्य मानते हैं। सब सामूहिक रूप से बिना किसी भेदभाव के स्नान, ध्यान और पूजन करते हैं। समरसता का यही भाव हिंदू संस्कृति की मूल विशेषता है। चराचर जगत में ईश्वरत्व के दर्शन करने वाला हिंदू कभी ऊंच-नीच के भाव से प्रेरित नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश कुछ समय से अस्पृश्यता के विजातीय द्रव्य ने हमारे समाज जीवन को प्रभावित किया है। अब यह धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इन तीर्थस्थलों पर सबकी पहचान केवल एक भक्त के रूप में ही रहती है। इन्हीं सब कारणों से ही कहा जाता है कि भारत की आत्मातीर्थों में ही निवास करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की चिति के रूप में जिस तत्व की चर्चा की थी, हमारे तीर्थ उस तत्व को मजबूत बनाते हैं। तीर्थों के इस महत्व को समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता।

(लेखक विश्व हिंदू परिषद् के संयुक्त महामंत्री हैं)



VALSAD DIST. COOP. MILK PRODUCERS' UNION LTD.

Vasudhara Dairy, Alipur, N.H. No. 8, Ta: Chikhli, Dist: Navsari

PROGRESS AT A GLANCE

PARTICULARS	UNIT	1981-82	2020-21
Capacity of Plant	TLPD	30	400
Paid up Share Capital	Rs. Lacs	5	4607
Reserve Fund	Rs. Lacs	1	6765
Other Funds	Rs. Lacs	22	19640
Total Turn Over	Rs. Crores	1.56	1787.29
Total Functional Societies	Nos.	143	1115
Coop Tribal Societies	Nos.	121	1037
Coop Women Societies	Nos.	0	921
Total Milk Procurement	'000 Kgs	2885	300316
From Tribal Societies	'000 Kgs	2164	246259
Cow Milk Procurement	'000 Kgs	202	163716
Average Milk Procurement	'000 Kgs	8	822.78
Price Paid to Milk Producers	Rs. Lacs	61	1014.29
Average Milk Marketing	000 LPD	7	667.27
Average Butter Milk Sales	000 LPD	-	76.31
Average Masti Dahi Sales	000 Kgs	-	30.40
Average Ghee Sales	000 Kg per Year	-	1666.13
Average Ice Cream Sales	000 LPD	-	45.69
Doudh Sanjeevani Flavord Milk Sales	000 LPD	-	000
Cattle Feed Production	000 MT per Year	-	97001





घुसपैठ और कब्जे को कानूनी जामा

चीन के नए सीमा कानून का उद्देश्य सिर्फ अन्य देशों में चीनी घुसपैठ और कब्जे को कानूनी जामा पहनाना है। चीन की मंशा यह है कि वह दूसरे देशों के इलाकों में घुसपैठ करे और उन इलाकों को अपना इलाका बताने के लिए इस कानून की आड़ ले। इससे भारत-चीन वार्ता में नए सिरे से गतिरोध पैदा होने का अंदेशा

■ आदर्श सिंह

इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह वैध है या अवैध हथकंडा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में लॉफियर यानी कानूनी औजारों का युद्ध के तरीकों के रूप में इस्तेमाल अब आजमाई हुई चीनी तरकीब बन चुका है। किसी भी जगह दावा ठोक देने और फिर वहां मछुआरे, पर्यटक भेजने, स्थायी निर्माण करने और रोके जाने पर इसे हजारों साल से चीन का अभिन्न अंग बताकर युद्ध की धमकी देने जैसे तरीके अब चीनी रणनीति का अहम हिस्सा हैं। मसलन, जापान के सेनकाकू द्वीप पर दावा ठोकने के प्रयास में चीन ने नवंबर 2013 में पूर्वी चीन सागर सहित जापानी जलक्षेत्र के एक हिस्से को एअर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (एडीआईजेड) घोषित कर दिया। यह किसी देश की वह सीमा होती है जिसमें घुसने पर किसी भी वायुयान को सूचित करना पड़ता है कि अब हम अमुक देश के वायुक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चीन का यह दांव कारगर साबित नहीं हुआ लेकिन फिर भी वह सेनकाकू को विवादित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में सफल हो गया है जबकि यह द्वीप 1895 से ही जापान के कब्जे में है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से यदि किसी क्षेत्र पर आपका पहले से कब्जा है तो 90 प्रतिशत कानून आपके साथ है। किसी अत्यंत विरल स्थिति में ही कोई दूसरा देश उस इलाके पर अपना दावा ठोक सकता है।

चीन ने 2012 में अमेरिकी अखबार द *न्यूयॉर्क टाइम्स* में दो पन्नों का विज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया था कि दियाओयू (सेनकाकू का चीनी नाम) हमेशा से चीन के कब्जे में रहा है। दावा ठोकने का सिलसिला अभी भी जारी है। 2020 में लगातार 100 दिन तक चीनी पोत सेनकाकू में जापानी जलक्षेत्र में दाखिल होते रहे और एक बार तो उसका एक पोत 39 घंटे तक जापानी जलक्षेत्र में खड़ा रहा। 2010 में मछली मारने वाली एक चीनी नौका के नशे में धुत कैप्टन ने एक जापानी गश्ती नौका को टक्कर मारी और हटने से इनकार कर दिया। जापान ने नौका के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया। इस



पर चीन की प्रतिक्रिया बेहद उग्र थी। उसने मंत्री स्तरीय संपर्कों को खत्म कर दिया, चीनी पर्यटकों को जापान जाने से रोक दिया और जापान को नतीजे भुगतने की धमकी दी। दो हफ्ते बाद जापान ने कैप्टन को रिहा कर दिया। कैप्टन ने रिहाई के बाद मासूमियत से कहा कि यह तो चीनी इलाका था, जापानियों ने आकर मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। उधर, चीनी सरकार ने कहा कि दियाओयू यानी सेनकाकू उसका है, इस बात को लेकर तो कोई विवाद ही नहीं। जापान हमारे जलक्षेत्र में घुस आया। उसने सिर्फ रिहाई की मांग ही नहीं की, बल्कि जापानी हिरासत में चीनी नौका के कैप्टन को जो शारीरिक-मानसिक कष्ट हुए, उसके लिए हर्जाना और जापान सरकार से माफी की भी मांग की। गनीमत यही रही कि जापान ने हर्जाना देने और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन ही ऐसा देश है जो उन इलाकों पर भी कब्जे का दावा ठोकता रहा है जो कभी उनके कब्जे में

थे ही नहीं। लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयों से वह इन इलाकों को लेकर भी विवाद खड़ा करने में सफल है।

ताइवान भी 1895 से 1945 तक जापान के कब्जे में रहा और उसके बाद से स्वतंत्र देश है। यानी वह कम से कम सवा सौ साल से अधिक चीन के कब्जे में कभी नहीं रहा। लेकिन चीन का दावा है कि ताइवान उसका अटूट अंग है। वह युद्ध का खतरा मोल लेकर भी ताइवान पर कब्जे पर आमादा है। दक्षिणी चीन सागर पर टुकड़ों-टुकड़ों में वह कब्जा करता ही जा रहा है। पहले कृत्रिम द्वीप बनाए, फिर उन पर सैन्य अड्डे बनाए और फिर उन्हें



अलग-अलग प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में चिह्नित कर दिया। अब वह दक्षिणी चीन सागर से गुजरने वाले तमाम पोतों को बताता है कि आप चीन की जलसीमा में हैं।

मछुआरे चीनी विस्तारवाद के हरावल दस्ते

चीनी कोस्टगार्ड यानी तटरक्षक बल और चीनी मछुआरे अब चीनी विस्तारवाद के हरावल दस्ते बन चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में सुनवाई के दौरान 2012 में एक एडमिरल ने कहा कि चीनी कोस्टगार्ड वास्तव में एक हैरेसिंग फोर्स बन चुकी है जिसका काम दक्षिण-पूर्वी एशिया के छोटे देशों को परेशान करना। सिर्फ परेशान करना ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों की जमीन पर कब्जे के लिए भी किया जा रहा है। चीन उन तमाम तरकीबों का प्रयोग अत्यंत निर्लज्जता के साथ कर रहा है जो सभी मान्य अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं। मसलन उसने अपने मछुआरों और मछली मारने वाली नौकाओं को जनमुक्ति सेना (पीएलए) के मिलीशिया दस्ते में तब्दील कर दिया है। ये किसी भी क्षेत्र पर दावा ठोकने में चीन के सबसे अहम औजार हैं। चीनी नौकाएं और मछुआरे किसी भी देश के जलक्षेत्र में घुस जाते हैं और हेकड़ी से कहते हैं कि यह हमारा इलाका है, सदियों से हमारे पुरखे यहां मछली मारते रहे हैं। क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि उनकी सुरक्षा के लिए पीछे चीनी कोस्टगार्ड के हथियारों से लैस पोत तैनात हैं।

इसी तरकीब से चीन ने 2012 में फिलीपीन के स्केरबोरो शोल पर कब्जा किया। चीनी मछुआरे और मछली मारने वाली नौकाएं स्केरबोरो शोल इलाके में घुस आईं और हटने से इनकार कर दिया। फिलीपीन ने उन्हें हटाने के लिए अपनी नौसेना के पोत भेजे लेकिन चीनी पोतों ने उसका रास्ता रोक दिया और स्केरबोरो शोल पर तब से उसका कब्जा है। यह चीनी लॉफियर यानी किसी की जमीन हड़पने के लिए कानूनी दलीलों के इस्तेमाल का नायाब नमूना है। चीन का कहना था कि निःशस्त्र मछुआरों को पकड़ने के लिए नौसेना के पोत भेजना कानूनी तौर पर अमान्य है और इसलिए चीन को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब समस्या यह है कि फिलीपीन के तटरक्षक बल के पास इक्के-दुक्के पोत हैं और वे भी राहत व बचाव कार्यों के उद्देश्य से बनाए गए हैं। लेकिन फिलीपीन को उकसाने की चीनी रणनीति कामयाब हो गई और स्केरबोरो सोल पर उसका कब्जा हो गया।

चीन का नया सीमा प्रबंधन कानून सीमावर्ती गांवों और सीमाई इलाकों के लोगों को यह अधिकार देता है कि वे आत्मरक्षा में कोई भी कार्रवाई यहां तक कि युद्ध भी करने को स्वतंत्र हैं। यानी अब कब्जा कर जिन इलाकों में चीन ने स्थायी निर्माण किए हैं या नए गांव बसाए हैं, उन्हें अब मिलीशिया की तर्ज पर ढाला जाएगा

चीन की रणनीति

चीन की रणनीति स्पष्ट है। जो मेरा है उस पर कोई समझौता नहीं और जो तुम्हारा है, उस पर हमें दावा ठोकना है और आपको समझौता करना है। और जिस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, उसे अब कानूनी वैधता देनी है। चीन ने 23 अक्तूबर को एक नया सीमा कानून पास कर यही कोशिश की है। यह फौजदारी से दीवानी का मुकदमा जीतने के प्रयास जैसा है। सात अध्यायों और 12 खंडों वाले इस कानून के अनुसार चीन की क्षेत्रीय अखंडता पवित्र और गैर-अवहेलनीय है। इस कानून की खास बात यह है कि इसमें सीमावर्ती गांवों और सीमाई इलाकों के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आत्मरक्षा में कोई भी कार्रवाई, यहां तक कि युद्ध भी, करने को स्वतंत्र हैं। यानी अब कब्जा कर जिन

इलाकों में चीन ने स्थायी निर्माण किए हैं या नए गांव बसाए हैं, उन्हें अब मिलीशिया की तर्ज पर ढाला जाएगा। चीन की सेना और सशस्त्र पुलिस इनकी सुरक्षा को हमेशा तत्पर रहेगी। यानी समुद्री इलाकों पर कब्जा करने के लिए जो काम अब तक चीनी मछुआरे और कोस्टगार्ड कर रहे थे, अब वही काम जमीनी सीमा पर पीएलए और मिलीशिया शुरू करेगी। चीन ने हालिया कुछ सालों में नेपाल और भूटान में तमाम जगहों पर अवैध कब्जा कर नए गांव बसाए हैं। यहां तक कि पिछले साल लद्दाख के पूर्वी सेक्टर में घुसपैठ के बाद उसने उस इलाके में स्थायी निर्माण के लगातार जारी रखा है। और सैन्य कमांडरों की वार्ता में चीन लगातार यह कह रहा है कि गलवान उसका अभिन्न अंग है।

भारत-चीन वार्ता में नया पेच

निश्चित रूप से अब सीमा पर वार्ता में चीन अपने नए घरेलू कानूनों की आड़ लेगा। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि अब सीमा वार्ता में भारत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत को अनुभव से पता है कि चीन के साथ सहृदयता दिखाने और वार्ता के नतीजे पहले भी कभी नहीं निकले हैं। इस कानून

नए कानून से स्पष्ट है कि दक्षिणी चीन सागर में समुद्री इलाकों पर कब्जा करने के लिए जो काम अब तक चीनी मछुआरे और कोस्टगार्ड कर रहे थे, जमीन पर अब वही काम पीएलए और मिलीशिया करेगी।

का भारत के लिए यही मतलब है कि आने वाले दिनों में चीन सलामी स्लाइसिंग यानी टुकड़ों में कब्जा करने की रणनीति पर अमल न सिर्फ जारी रखेगा बल्कि यह और भी बढ़ेगी। लद्दाख में 17 महीने से जारी गतिरोध के समाधान के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच हुई बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने से साफ मना करते हुए संकेत दिए कि अब हम आपकी सीमा में दाखिल हो गए हैं और आप ताकत के जोर से हमें हटा नहीं सकते। इसलिए मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर लें। अप्रैल 2020 की स्थिति की बहाली की भारत की मांग को अतार्किक और अवास्तिवक करार देते हुए उसने कहा कि वह अपनी संप्रभुता व अखंडता की हर हाल में सुरक्षा करेगा। लगे हाथ उसने भारत को यह नसीहत भी दे डाली कि जिन इलाकों से चीनी सेना पीछे हट गई है, उससे भारत को संतुष्ट हो जाना चाहिए। चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जब दो बड़े देशों के बीच सीमा विवाद होता है तो उसे उसी तरह सुलझाना चाहिए जैसे दो बड़ी शक्तियां सुलझाती हैं। लेकिन आगे वह भारत को एक तरह से औकात में रहने की चेतावनी देते हुए लिखता है, भारत की सैन्य क्षमताएं सीमित हैं लेकिन वह देशभक्ति का सुपरपावर बन गया है। क्या यह तंज प्रधानमंत्री मोदी पर है? अखबार आगे लिखता है कि अगर भारत को पश्चिमी सीमा पर शांति चाहिए तो उसे चीन की मांगों पर समझौता करना पड़ेगा। इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है। आगे के दिनों में घुसपैठ के प्रयास और बढ़ेंगे। और ये बढ़ भी रहे हैं। यहां तक कि वह तवांग जैसे इलाके जहां कि भारतीय फौज की मजबूत उपस्थिति है, वहां भी वह घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड के बाराहोती तक में घुसपैठ की कोशिश हुई है। 'हैरेसिंग फोर्स' के रूप में जो काम चीनी मछुआरे और कोस्टगार्ड दक्षिणी चीन सागर में कर रहे थे, वही काम पीएलए अब हिमालय में कर रही है।

चीन की मंशा

दीवार पर लिखी इबारत साफ है। चीन का मानना है कि इस समय वह सैन्य-आर्थिक रूप से मजबूत है तो भारत को उसकी शर्तों पर समझौता करना होगा। चीन को अभी भी लगता है कि 1962 दोहराया जा सकता है। पिछले 17महीने से वह सीमा पर और तिब्बत में भांति-भांति के सर्कस कर रहा है। उसका मकसद भारत को अपनी सैन्य ताकत दिखाना है। यही डोकलाम गतिरोध के समय भी हुआ जब ग्लोबल टाइम्स दावे करता था कि पर्वत अपनी जगह से हिल जाएंगे लेकिन पीएलए नहीं हिलेगी। हटने वाली तो भारतीय सेना भी नहीं। हटना तो दूर, चीनी फौज की नाक के ऐन नीचे कैलाश रेंज की तमाम चोटियों पर कब्जा करके हमने पीएलए को बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। चीन भारत को सीमा पर परेशानी में डालकर यह दिखाना चाहता है कि वह एशिया की निर्विवाद ताकत है। साथ ही तैयारियों के पीछे मंशा ऐसी दिखती है कि वह किसी भी समय युद्ध छेड़ सके और 1962 की तरह देखते ही देखते जंग जीत ले। निश्चित रूप से किसी भी समय के मुकाबले आज भारत-चीन के बीच युद्ध की संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। चीनी सेना की लगातार घुसपैठ की रणनीति पाकिस्तान की हजार घाव देने जैसी रणनीति ही है। भारत को कहीं न कहीं चीन को करारा जवाब देना ही पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक बार फिर 1962 जैसी स्थिति दोहराने के प्रयास में है। उनका मानना है कि हम भले न चाहें लेकिन सीमा पर एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला है और यह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल के दौरान ही होगा। चीन के दो उद्देश्य हैं। पहला, उसका मानना है कि युद्ध से मोदी की लोकप्रियता घट जाएगी और हो सकता है कि वे सत्ता भी गवां बैठें। दूसरा, भारत की पराजय से अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों को यह संदेश जाएगा कि चीन से मुकाबले के लिए भारत पर दांव लगाने का कोई फायदा नहीं। हमें सीमा पर अपनी तैयारियों से चीन को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसी कोई भी भूल उसे बहुत महंगी पड़ेगी।

(लेखक साइंस डिवाइन फाउंडेशन से जुड़े हैं)

सादगी, संयम और सेवा के प्रतीक

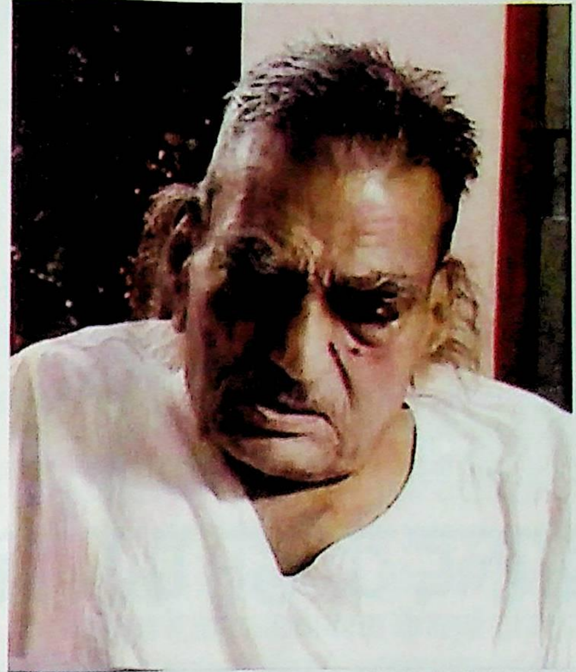
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री ओमप्रकाश गर्ग का छह नवंबर को पटना में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. आ. एन. सिंह ने बताया कि उन्हें श्वास संबंधी मामूली बीमारी थी।

श्री गर्ग मूलतः गाजियाबाद के रहने वाले थे। कानपुर से पढ़ाई समाप्त करके वे संघ के प्रचारक बने और उत्तर प्रदेश में संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। इसके बाद 1966 में उन्हें भारतीय जनसंघ का दायित्व दिया गया। 1967 में उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

70 के दशक में उन्हें संघ कार्य के लिए बिहार भेजा गया था। इसके बाद वे बिहार में पूरी तरह रम गए। आपातकाल के दिनों में उन्होंने भूमिगत रहकर लगातार संघर्ष किया। पटना, गया और शाहबाद में संघ की जितनी गुप्त बैठकें होती थीं, उसके सूत्रधार ओमप्रकाश जी ही होते थे।

श्री गर्ग 1980 में बिहार के प्रांत प्रचारक बने। उनके नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में दो बड़े कार्यक्रम हुए, जिनकी चर्चा आज भी की जाती है। 1980 में पूर्वांचल शिशु संगम हुआ था। गांधी मैदान में 5,000 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई थी। पटना की तत्कालीन आयुक्त राधा सिंह ने उनके संगठन कौशल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें अजातशत्रु कहा था। इसके बाद 1982 में गांधी मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें सांसद महाराजा कर्ण सिंह, जोधपुर के महाराजा तथा बिहार के सांसद शंकर दयाल सिंह जैसे नेता उपस्थित थे।

श्री गर्ग को 1992 में संघ कार्य के लिए नेपाल भेजा गया। उन्होंने वहां अत्यंत कर्मठता के साथ कार्य प्रारंभ किया, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। नेपाली भाषा और हिंदी साहित्य के समन्वय को लेकर वे सतत सक्रिय रहे। उन दिनों भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में देशविरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। इस कारण उन्हें 2002 में सीमा जागरण मंच का कार्य सौंपा गया। उस समय श्री गर्ग का केंद्र लखनऊ था। उन्हें 2005 में विश्व हिंदू परिषद् का दायित्व मिला। वे 2006 में प्रौढ़ कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय प्रमुख बने। 2007 के प्रयाग कुंभ में तृतीय हिंदू विश्व सम्मेलन का आयोजन किया



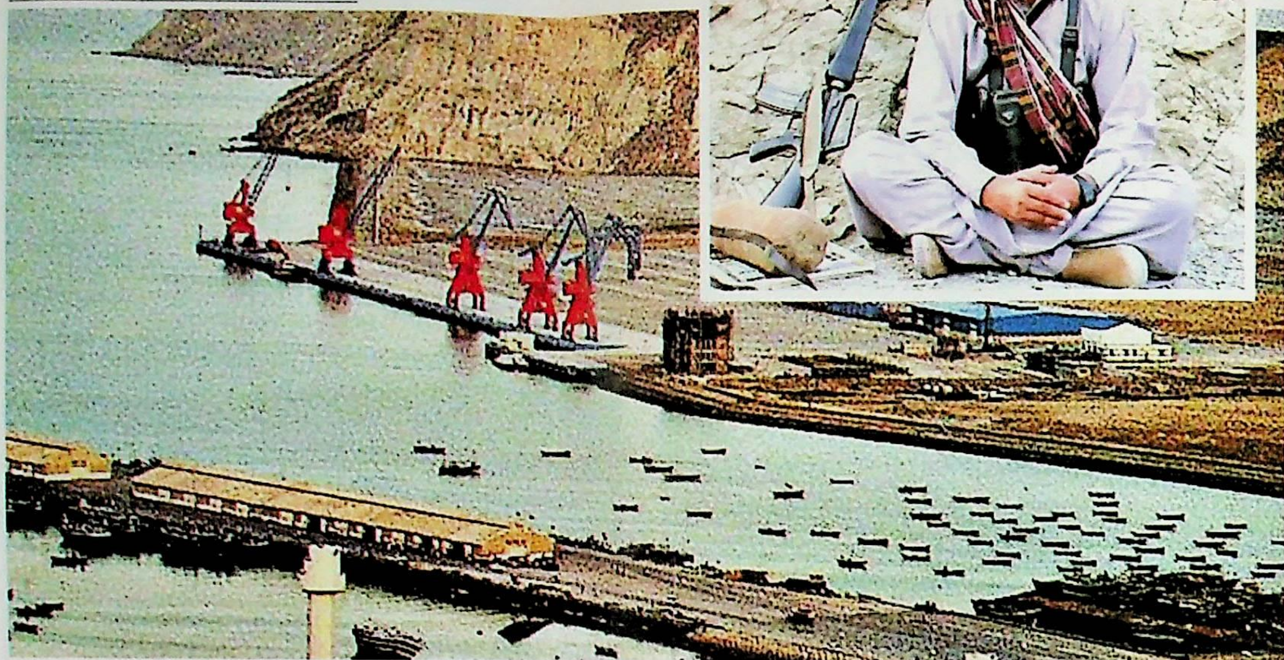
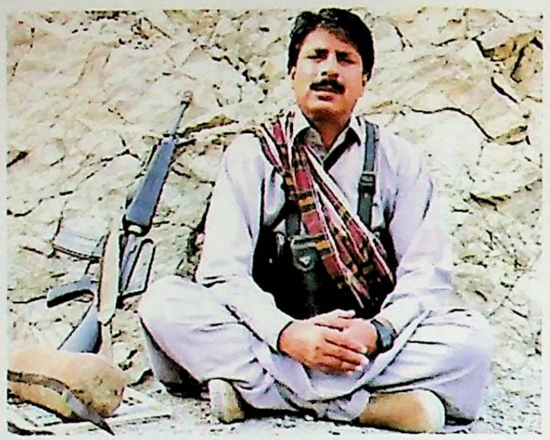
स्वर्गीय ओमप्रकाश गर्ग

गया था। इसमें बिहार के कार्यकर्ताओं ने लगातार बारिश में भी उनके नेतृत्व में सेवा कार्य किया। 2010 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद् का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बाद बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने पद को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। ओमप्रकाश जी का इस क्षेत्र में सघन संपर्क था। बिहार में ऐसे हजारों घर हैं, जहां उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है। सबके सुख-दुःख में शामिल होना उनका स्वभाव था। वे सादगी, संयम एवं समन्वित जीवन के पर्याय थे। उनके व्यक्तित्व ने कई लोगों को प्रभावित किया। सैकड़ों युवक उनके जीवन से प्रभावित होकर सामाजिक कार्य में लगे। उनके प्रयासों से ही विश्व हिंदू परिषद् का प्रांतीय कार्यालय पटना में बना।

उन्होंने दधीचि देहदान समिति के आह्वान पर मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया था। इस कारण उनके शव को सात नवंबर को पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को दान कर दिया गया।

-संजीव कुमार

प्रस्तुति : अरविन्द

बलूचिस्तान प्रांत से सीपीईसी का एक बडा हिस्सा गुजरता है। प्रकोष्ठ में डॉ. अल्लाह नजर बलोच (फाइल फोटो)

बारूद के ढेर पर है सीपीईसी

विवादित जमीन से होकर गुजरने वाले सीपीईसी से लगते इलाकों में पाकिस्तानी फौज और बलूचों के बीच आए दिन हो रहा छिटपुट संघर्ष किसी बड़े वारदात का संकेतक

इन दिनों पाकिस्तान की फौज और आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलूच लड़ाकों के बीच आए दिन छोटी-मोटी झड़पें हो रही हैं। बेशक दो माह पहले खैबर पख्तूनख्वा में चीनियों पर हुए जोरदार हमले के बाद कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी चीनी महफूज नहीं है। खास तौर पर सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) के लिए तो यही कहा जा सकता है कि लंबे घुमावदार समुद्री रास्ते और मलक्का जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत बनाया गया यह रूट बारूद के ढेर पर है और कभी भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है।

बलूचिस्तान की आजादी के लिए छापामार संघर्ष कर रहे लोकप्रिय नेता डॉ. अल्लाह नजर बलोच कहते हैं, ''सीपीईसी सिर्फ और सिर्फ चीन और पंजाब की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। अब तक जितने प्रोजेक्ट बने और बन रहे हैं, वे सारे पंजाब में ही बने हैं। सीपीईसी के किनारे हमारे लोगों को बसने तो नहीं ही दिया जा रहा है, उलटे मकामी (स्थानीय) लोगों को वहां से भाग जाने को मजबूर किया जा रहा है। उनका कत्ल हो रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है। हालात यह है कि सीपीईसी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद दूसरे इलाकों में जाकर बसने को मजबूर है। यहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। बलूच अपनी कौमी शिनाख्त से महरूम हो रहे हैं और दुनिया का इस तरफ ख्याल नहीं है।''

हाल ही में चीन ने कराची को सीपीईसी योजना के अंतर्गत विकसित करने का फैसला किया है। इसका दूसरा पहलू यह है कि ग्वादर की सुरक्षा में बलूच लगातार सेंध लगाने में कामयाब होते रहे हैं। दो साल पहले वहां के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से लेकर दो माह पूर्व एक चीनी बस पर हुए हमले तक, बलूच खौफ का माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान-चीन ने अपनी योजना में ग्वादर को थोड़ा पीछे कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरह सीपीईसी के बाकी हिस्से की सुरक्षा को पुख्ता करना चाहता है। इसी वजह से

उसने सीपीईसी पर तैनात फौजियों की संख्या में खासा इजाफा किया है। बलूच नेशनल मूवमेंट के नेता हुनक बलोच कहते हैं, ''पाकिस्तान ने ग्वादर की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन फौजियों को लगा रखा है। इसके बावजूद कौमी आजादी के लिए सिर पर कफन बांधकर जद्दोजहद करने वाले बलूच यह बताने में कामयाब रहे हैं कि वहां रहने वाले चीनी महफूज नहीं हैं। सीपीईसी में कराची को शामिल करना बताता है कि चीन और पाकिस्तान ग्वादर में जो कुछ भी करना चाह रहे थे, वैसा नहीं हो पा रहा। इसीलिए पाकिस्तान पूरी ताकत लगाकर सीपीईसी के बाकी रास्ते को महफूज करना चाहता है।''

डॉ. अल्लाह नजर बलोच का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी फौज बलूचों का हौसला तोड़ने के लिए औरतों और मासूमों को निशाना बना रही है, उससे बलूचों में आजादी हासिल करने का जज्बा और मजबूत हुआ है। यह दिखता भी है। हाल ही में तुरबत के होशाब इलाके में पाकिस्तान फौज के मोर्टार हमले में 5 साल के अल्लाहबख्श और उसकी 7 साल की बहन शरतून की मौत हो गई तो इसके खिलाफ जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तुरबत इलाके में ही एक साल पहले 4 साल की ब्रम्श को पाकिस्तान फौज की रहनुमाई में काम करने वाले डेथ स्क्वायड ने गोली मारकर घायल कर दिया था। तब भी लोगों में काफी उबाल था और ब्रम्श एक तरह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़ाने की लड़ाई की प्रतीक बन गई थी। डॉ. अल्लाह कहते हैं, ''इन्सानी हुकूक की पैरोकारी करने वाले अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि अगर जॉर्ज वाशिंगटन ने जद्दोजहद नहीं की होती तो वह आज कहां होता? हम भी अपनी कौमी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और बलूचों को इस बात का पूरा हक है कि वे अपनी जमीं से पाकिस्तान के गैर-वाजिब कब्जे को हटाने की लड़ाई लड़ें।''

सीपीईसी पर सुरक्षा बढ़ाने के मामले में हुनक कहते हैं, ''वैसे तो पूरा बलूचिस्तान ही सुलग रहा है। लेकिन खास तौर पर सीपीईसी का पूरा रास्ता तो जैसे बारूद के ढेर पर है। मकामी लोगों में कई बातों को लेकर गुस्सा है। इनमें एक वजह यह भी है कि बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल को लूटा जा रहा है और इस पर पूरा पाकिस्तान गुजर कर रहा है लेकिन उन्हें ही इसका फायदा नहीं मिल रहा, जहां से इन्हें निकाला जा रहा है। वे हथियार से लड़ रहे हैं और बलूच जुनून से। जाहिर है, सीपीईसी पर कोई बड़ी वारदात का होना बस वक्त की बात है।''

बलूचिस्तान के पास जो कुदरती वसाइल हैं, ऐसा लगता है कि वही इसके दुश्मन साबित हुए हैं। अंग्रेजों के इस इलाके में आने के पहले से ही यह इलाका बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता था। सन् 1908 के गजट में अंग्रेजों ने इस बात का जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में 1887 से 1903 के बीच कुल मिलाकर 2,46,426 टन कोयले का उत्पादन हुआ और तकरीबन यह पूरा कोयला नॉर्थ-वेस्टर्न रेलवे के काम आया। अंग्रेजों ने खनिजों की ढुलाई के लिए यहां भी जमकर रेलवे का इस्तेमाल किया था। पेट्रोलियम के मामले में भी बलूचिस्तान धनी रहा है और अंग्रेजों ने 1886 में 27,700 गैलन पेट्रोलियम निकाला था जो 1891 तक बढ़कर 40,465 गैलन हो गया था। 1886 से 1892 के बीच 7,77,225 गैलन पेट्रोलियम निकाला गया। इसके अलावा भी चूना पत्थर, तांबा, लोहा जैसे तमाम खनिजों का बलूचिस्तान में विशाल भंडार है।

वक्त बदल गया लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान का इनसानों को लेकर नजरिया। एक वक्त था जब उसे पूर्वी पाकिस्तान की जमीन चाहिए थी, वहां के लोग नहीं और इसका नतीजा यह हुआ कि स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया और कालांतर में उसी जमीन पर नए देश बांग्लादेश ने जन्म ले लिया। आज बलूचिस्तान में उसे

पाकिस्तानी, बलूचों की नस्लकुशी कर रहे हैं। बलूचों की रवायतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी जिंदा कौम की ही तरह बलूच कभी भी अपनी औरतों, अपने बच्चों के साथ हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलूचों ने अब तक अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। आगे भी लड़ेंगे। लेकिन दुनिया को जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना बेहतर कि बलूचों की जद्दोजहद दरअसल इन्सानियत की लड़ाई है, इन्साफ की लड़ाई है

बलूचों की जमीन चाहिए, उनके प्राकृतिक संसाधन चाहिए जिससे वह पूरे देश को सुविधा दे सके, लेकिन उसे बलूच नहीं चाहिए। यही कारण है कि वह पूरे इलाके की जनसांख्यिकी को बदलना चाहता है। बलूचों को डरा-धमकाकर, उनके साथ जोर-जबर्दस्ती करके, उनके खिलाफ तरह-तरह के जुल्म करके उन्हें बलूचिस्तान से हटाना चाह रहा है। डॉ. अल्लाह नजर बलोच के अनुसार, ''वे बलूचों की नस्लकुशी कर रहे हैं। बलूचों की रवायतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी जिंदा कौम की ही तरह बलूच कभी भी अपनी औरतों, अपने बच्चों के साथ हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बलूचों ने अब तक अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। आगे भी लड़ेंगे। लेकिन दुनिया को जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना बेहतर कि बलूचों की जद्दोजहद दरअसल इन्सानियत की लड़ाई है, इन्साफ की लड़ाई है। क्या आपने पाकिस्तान के दहशतगर्द रुख को नहीं देखा? क्या नहीं देखा कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी को सियासी औजार की तरह इस्तेमाल करता है?' ■

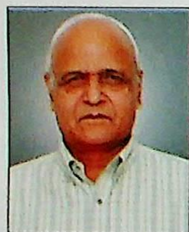

कनिष्क कालीन शिव एवं राजा कनिष्क के 200-220 ईस्वी के मुद्रांकित सिक्के


हिन्दूशाही कालीन 9वीं सदी की एकमुखलिङ्ग शिव प्रतिमा


राजा खिंगलकालीन की 5वीं सदी की महाविनायक की प्रतिमा


तालिबान द्वारा ध्वस्त बामियान की बुद्ध की प्रतिमाएं

वैदिक युग से हिन्दूशाही तक अफगानिस्तान में रही हिंदू सभ्यता


■ प्रो. भगवती प्रकाश

अफगानिस्तान कांस्य युग व सिन्धु घाटी सभ्यता के काल में हिन्दू सभ्यता व संस्कृति का केन्द्र रहा है। अफगानिस्तान का संदर्भ ऋग्वेद में भी आता है। काबुल, गजनी, कन्धार से मध्य एशिया तक उत्खननों में मिले शिव-पार्वती, महिषासुरमर्दिनी, ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण सहित विविध हिन्दू देवी-देवताओं के पुरावशेषों में कुछ को काबुल व गजनी से ताजिकिस्तान तक के संग्रहालयों में देखा जा सकता है।

नोब्रास्का विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् प्रो. जॉन फोर्ड श्रोडर के अनुसार अफगानिस्तान में मानव सभ्यता का इतिहास 50,000 वर्ष प्राचीन है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् विलियम लिओनार्ड लेंगर के अनुसार भी अफगानिस्तान- गान्धार में मानव सभ्यता का इतिहास 34,000 वर्ष प्राचीन है। वैदिक काल से 1026 ई. हिन्दूशाही तक वहां हिन्दू व बौद्ध साम्राज्य एवं बीसवीं सदी तक हिन्दू, बौद्ध व सिख परम्पराएं सजीव रही हैं।

हिन्दू सभ्यता का केन्द्र

जोनाथन केनोयर मार्क के अनुसार कांस्य युग व सिन्धु घाटी सभ्यता के काल में अफगानिस्तान हिन्दू सभ्यता व संस्कृति का केन्द्र रहा है। महाभारतकालीन महाजनपद गान्धार से आगे प्राचीन मेसापोटामिया अर्थात् वर्तमान ईराक व तुर्की तक 1550-551 ईसा पूर्व काल में हिन्दुत्व के प्रसार का इतिहासकार जेम्स मिनाहन ने 2002 में प्रकाशित अपने 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेटलेस नेशन्स' में विस्तार से विवेचन किया है।

ईसा पूर्व 1380 के हित्ती व मित्तानी राजाओं क्रमशः 'सुप्पिलिआ' और शत्तिवाज के बीच हुए सन्धि पत्र में वैदिक देवता 'मित्र', 'इन्द्र' नासत्य-अश्विनी कुमार व अग्नि आदि के साक्षी आदि, गान्धार से आगे मेसापोटामिया तक वैदिक सभ्यता के अनेक प्रमाण विगत 4-5 दशकों में प्रकाश में आते रहे हैं। हाल ही में 2000 ईस्वी में मजार-ए-शरीफ में मिले हिन्दूशाही के राजा वाक्कदेव के दसवीं सदी के शिलालेख में शिव-पार्वती एवं मां दुर्गा के प्रचुर सन्दर्भ हैं। प्राचीन 'उत्तरापथ' अर्थात् सिल्क रूट पर यह 'उप गणस्थान' कहलाने वाला अफगानिस्तान ईरान व यूरोप तक व्यापार व सांस्कृतिक विनिमय का केन्द्र रहा है।

वैदिक व पौराणिक सन्दर्भ

पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक फैले गान्धार की उत्तम ऊन वाली भेड़ों एवं पराक्रमी व न्यायप्रिय नारियों के ऋग्वेद व अथर्ववेद में भी सन्दर्भ हैं। यह ऋग्वेद काल से ही हिन्दू संस्कृति व वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद बौद्ध सभ्यता का केन्द्र रहा है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 127वें सूक्त में गान्धार का उल्लेख मिलता है:-

मन्त्रः-

उपोप मे परा मृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः। सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका।। ऋग्वेद 1/126/7।।

भावार्थः हे राजन्! मैं गान्धारवासिनी इस पृथ्वी का राज्य धारण करने व न्यायपूर्वक रक्षा करने में सक्षम हूं। प्रशंसित रोमों वाली, सब प्रकार के गुणों की धारक उत्तम भेड़ों से युक्त इस क्षेत्र की सम्राज्ञी हूं। मेरे कामों को छोटे में मत आंको।

वायु पुराण, अन्य पुराणों, महाभारत एवं अन्य संस्कृत ग्रन्थों व पाण्डुलिपियों मे और उप गणस्थान के नाम से अफगानिस्तान के


काबुल म्यूजियम में गजनी से प्राप्त दूसरी सदी की मां दुर्गा की प्रतिमा का शीश


मजार-ए-शरीफ से प्राप्त 10वीं सदी का हिन्दूशाही कालीन शिलालेख

प्रचुर सन्दर्भ हैं। महाभारत में गान्धारी एवं गान्धार राजकुमार शकुनि के भी सन्दर्भ हैं। पाकिस्तान स्थित मुल्तान, पुष्कलवती, तक्षशिला व रावलपिण्डी प्राचीन महाजनपद गान्धार में ही थे। मुल्तान में प्रह्लादपुरी का प्राचीन नृसिंह मन्दिर विश्वप्रसिद्ध रहा है, जहां हिरण्यकशिपु की राजधानी थी, वहीं नृसिंह मन्दिर था एवं विभाजन के पूर्व नृसिंह जयन्ती पर मेला लगता था। बाबरी ढांचा ध्वस्त होने पर इस मन्दिर को पाकिस्तान में उपद्रवकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। नृसिंह पुराण व भागवत पुराण में भी नृसिंह अवतार के सन्दर्भ हैं।

हिन्दू पौराणिक व बौद्ध प्रतिमाओं के पुरावशेष

काबुल, गजनी, कन्धार से मध्य एशिया तक उत्खननों में मिले शिव-पार्वती, महिषासुरमर्दिनी, ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण सहित विविध हिन्दू देवी-देवताओं के पुरावशेषों में कई काबुल व गजनी से ताजिकिस्तान तक के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। पांचवीं से आठवीं सदी के बीच हिन्दूशाही कालीन व बौद्ध पुरावशेष पूरे अफगानिस्तान में फैले हैं। कनिष्क कालीन तीसरी सदी के सिक्कों (चित्र1) में शिव, शिव-पार्वती के स्वर्ण के सिक्के, नौवीं सदी का शिव का एकमुखलिंग (चित्र 2), पांचवी सदी की संगमरमर की विशाल गणेश प्रतिमा (चित्र 3), बामियान की बौद्ध प्रतिमाएं (चित्र 4), अशोक के शिलालेख, गजनी में प्राप्त दूसरी सदी का मां दुर्गा का शीष, जो काबुल के संग्रहालय में है (चित्र 5) आदि अफगानिस्तान व मध्य एशिया के वैदिक हिन्दू-बौद्ध इतिहास के असंख्य सजीव प्रमाण हैं।

मजार-ए-शरीफ का हिन्दूशाही कालीन शिलालेख

हिन्दूशाही कालीन राजा वेक्कराज के शारदा लिपि में उत्कीर्णित ईस्वी 959 के संस्कृत शिलालेख (चित्र 6) के वर्ष 2000 में मजार-ए-शरीफ से मिलने के बाद अफगानिस्तान की हिन्दूशाही एवं वहां शिव, विष्णु, मां दुर्गा सहित विविध देवी-देवताओं पर नवीन तथ्य सामने आए हैं। इस शिलालेख से पता चलता है कि हिन्दूशाही के राजा 'कल्लर' का काल 843 से नहीं, 821 से था। सातवीं सदी की तुर्कशाही के बौद्ध शासकों के अधीन मुस्लिम आक्रान्ताओं के बढ़ते आक्रमण व पुरुष-स्त्रियों को गुलाम बनाकर ले जाने के संकट के चलते तुर्कशाही के बौद्ध सम्राट ने सत्ता ब्राह्मण मन्त्री 'कल्लर' को हस्तान्तरित कर दी। तब 821 से कल्लर से चली हिन्दूशाही में मुस्लिम हिंसा का दौर थमा और 1026 तक वाक्कदेव, कमलवर्मन, भीमदेव, जयपाल, आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल व भीमपाल ने अफगान प्रजा की रक्षा की। 28 नवम्बर, 1001 को महमूद गजनवी ने धोखे से राजा जयपाल को पेशावर के युद्ध में बड़ी क्षति पहुंचाई थी। तब से अफगानिस्तान में बलात इस्लामीकरण का दौर चल पड़ा। इतिहासकार अल उत्बी के अनुसार महमूद ने पेशावर से वैहिन्द तक आक्रमण कर 5 लाख हिन्दू बच्चों, युवकों व लड़कियों को गुलाम बनाया और 1014 में थाणेसर के युद्ध में 2 लाख और गुलाम बनाये। गजनी के सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने 971 से 1030 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पेशावर पर 1000 में, 1005 में भाटिया, 1006 में मुल्तान, 1007 में भटिण्डा, 1011 में नगरकोट, 1013 में वैहिन्द पर 1015 में कश्मीर, 1018 में कश्मीर एवं 1021 मे कन्नौज पर आक्रमण किया।

इन लुटेरों ने अपने आक्रमणों में नगरों व गांवों को लूटना, युवकों व लड़कियों को अपहत कर गुलाम बनाना, इन गुलामों व उनकी सन्तति से सम्प्रदाय की संख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी कई गुनी वृद्धि कर उत्तरोत्तर बड़े से बड़े आक्रमण करना, फिर लूटपाट करना व गुलाम बनाकर संख्या बढ़ाते जाने के 7वीं सदी से चले दुष्चक्र से इण्डोनेशिया से अफगानिस्तान तक अरब व अन्य जिहादी आक्रमणों से अधिकाधिक शक्ति अर्जित कर वृहत्तर भारत में 7वीं सदी से एक हजार वर्ष तक आक्रमण एवं बलात मतान्तरण करने में सफलता पाई।

हिन्दू, बौद्ध व सिख वर्चस्व का काल

मौर्य साम्राज्य में 303 ईसा पूर्व से 1026 में हिन्दू शाही का अन्त होने तक अफगानिस्तान पर हिन्दू व बौद्ध शासन रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने नौशेरा के युद्ध के बाद काबुल नदी तक पुनः हिन्दू-सिख वर्चस्व स्थापित किया था। दोस्त मुहम्मद को परास्त कर सिख साम्राज्य में कई मन्दिरों व गुरुद्वारों का पुनर्निर्माण हुआ। अफगानिस्तान में 1970 तक 2,20,000 हिन्दू, बौद्ध व सिख थे और लोया जिरगा में 2 हिन्दू होते थे। व्यापार व स्थानीय शासन और जनजीवन पर 1950 तक हिन्दुओं का प्रभाव रहा है। नेताजी सुभाष अफगानिस्तान के रास्ते ही जर्मनी जाते समय कई दिन तक भक्तराम के घर रहे थे।

आज चाहे वहां तालिबान का आतंक है। लेकिन, इण्डोनेशिया से अफगानिस्तान तक के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास की स्मृतियों को सम्पूर्ण वृहत्तर भारत में अक्षुण्ण रखना व उन पर सतत अनुसन्धान इस क्षेत्र के सभी मत पंथों के बुद्धिजीवियों का अहम दायित्व है।

(लेखक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के कुलपति हैं)



तकनीक



■ बालेन्दु शर्मा दाधीच

स्पियर फिशिंग: साइबर सुरक्षा आगे, जालसाज पीछे

आजकल स्पियर फिशिंग बहुचर्चित है। इसमें आपसे जुड़ी सूचनाओं के साथ संदेश मिलते हैं जिन पर आप सहज ही विश्वास करने के चलते फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए शंकालु बन पूरी पड़ताल करें

तकनीकी दुनिया में भी फिशिंग होती है। इसका इस्तेमाल अनभिज्ञ लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया जाता है। हालांकि दोनों फि शिंग की वर्तनी अलग-अलग है। बहरहाल, इन दिनों एक खास किस्म की फिशिंग चर्चित है–स्पियर फिशिंग। ऐसा माना जा रहा है कि यह ज्यादा घातक है और इसे पकड़ पाना ज्यादा मुश्किल।

फिशिंग

हालांकि आप फिशिंग से परिचित हैं लेकिन फिर भी बतौर संदर्भ बताना ठीक रहेगा। कुछ साइबर अपराधी ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया या सोशल मैसेजिंग के जरिए आपको ऐसे संदेश भेजते हैं जो किसी बैंक, सरकारी विभाग, बड़ी कंपनी आदि से आए हुए दिखाई देते हैं। जैसे ऐसा संदेश जिसमें आयकर विभाग के लोगो का इस्तेमाल किया गया है और वह ऐसे दिखता है जैसे आयकर विभाग ने ही आपको भेजा है। इसमें ऐसी सूचना दी जाती है जिसे अनदेखा करना आपके लिए मुश्किल होता है, जैसे यह कि आपको इनकम टैक्स रिफंड भेजा जा रहा है या फिर यह कि आपका रिटर्न सही ढंग से नहीं भरा गया था। वहीं एक लिंक देकर कहा जाता है कि आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। आप वेबसाइट पर पहुंचते हैं और अपनी लॉगिन डिटेल भी डाल देते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि यह असली आयकर विभाग की साइट नहीं है बल्कि साइबर अपराधियों ने हू-ब-हू असली साइट जैसी दिखने वाली नकली साइट बना डाली है। आपकी लॉगिन इन्फॉरमेशन को वे अपने पास सहेज लेते हैं और उसके बाद इनका दुरुपयोग कर सकते हैं।

स्पियर फिशिंग

लेकिन स्पियर फिशिंग इससे एक कदम आगे बढ़कर है। जहां फिशिंग में एक ही तरह का संदेश लाखों, करोड़ों लोगों को भेजा जाता है, वहीं स्पियर फिशिंग में एक खास कंपनी, खास वर्ग, समूह, शहर, आय वर्ग आदि के लोगों को निशाना बनाया जाता है। मसलन, अगर आप रिलायंस कंपनी में काम करते हैं तो आपको इसी कंपनी के नाम से ही नकली ईमेल भेजी जाती है। इसे तैयार करने पर खासी रिसर्च की जाती है और ईमेल में दी गई सूचनाएं एकदम सटीक प्रतीत होती हैं। मान लीजिए कि कंपनी के तिमाही वित्तीय नतीजे 30 तारीख को आने वाले हैं। अगर उसी दिन आने वाली ईमेल में इनका जिक्र किया गया हो तो पाने वाला उन्हें सही मान बैठेगा और वहां दिए लिंक पर क्लिक कर देगा।

किसी राजनैतिक दल से जुड़े कार्यकर्ताओं को उसी राजनैतिक दल के बारे में ईमेल मिले या फिर किसी शहर के लोगों को उसी शहर के नगर निगम की तरफ से ईमेल मिले तो जाहिर है, उनके भ्रमित होने के आसार ज्यादा होंगे। स्पियर फिशिंग का इस्तेमाल करने वाले हैकर अनभिज्ञ लोगों को ठगने के लिए इसी भ्रम का लाभ उठाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको यह संदेश मिले कि आप अगले सोमवार को कोलकाता आ रहे हैं तो अगर आप चाहें तो वहां के फलां होटल को बहुत सस्ती दर पर बुक कर सकते हैं। यह रही एक शानदार डील। आपने चूंकि अपनी कोलकाता यात्रा की योजना को सोशल मीडिया पर साझा किया था, इसलिए आपको लगेगा कि आपका कोई मित्र या शुभचिंतक, जो किसी होटल में काम करता होगा, उसने यह संदेश भेजा है। लेकिन समझदारी इस बात में है कि ऐसे संदेशों पर प्रतिक्रिया करने में जल्दबाजी न दिखाएं।

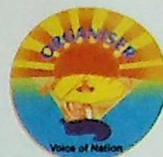
शंकालु बने रहें

स्पियर फिशिंग से बचने के उपाय भी वही हैं जो फिशिंग, स्पाईवेयर, वायरस और इंटरनेट के जरिए होने वाली दूसरी साइबर चुनौतियों से बचने के हैं। पांच बातें गांठ बांधकर रखिए- पहली आपके सिस्टम में एक दमदार सिक्यूरिटी सोल्यूशन होना चाहिए। आपके पास विंडोज 10 है तो उसमें पहले से ही विडोज डिफेंडर मौजूद है जो अब काफी सशक्त बन चुका है। अलग से कोई सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इन्स्टाल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात- अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। आप जानते हैं कि विंडोज और ऑफिस आदि के लिए समय-समय पर इंटरनेट से अपडेट डाउनलोड होते रहते हैं। तीसरी बात- किसी भी फाइल को आंख मूंदकर किसी बाहरी स्रोत से डाउनलोड या कॉपी करने से बचें। सुरक्षा संबंधी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही आगे बढ़ें। चौथी बात- ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर किसी भी लिंक को क्लिक करने से बचें जब तक कि आपको पक्का भरोसा न हो कि वह एक सुरक्षित लिंक है और वास्तव में उसी चीज का लिंक है जिसका दावा किया गया है। पांचवीं सावधानी यह है कि अगर कोई भी पेशकश, तथ्य, डील या बात अगर ज्यादा ही आकर्षक लग रही है तो वह शायद ही सच होगी। इंटरनेट तथ्य पर यकीन करने की बजाए शंकालु बने रहें, संदेह से काम लें।

(लेखक सुप्रसिद्ध तकनीक विशेषज्ञ हैं)



भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड

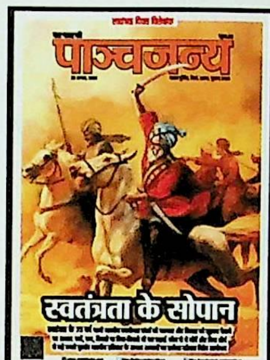


द एड्रेस
प्लॉट नंबर- 4बी, डिस्ट्रिक सेंटर, मयूर विहार, फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-91
संपर्क : 8143232814 ई-मेल: support@bpdl.in

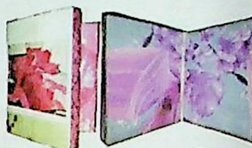
सब्सक्रिप्शन ऑफर एवं फार्म

क्रमांक: ....

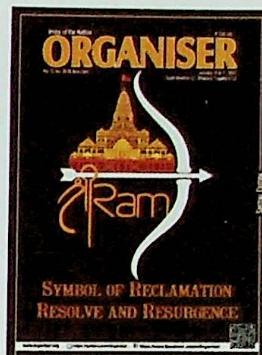
मूल्य ₹50



52% छूट
साथ में 4 विशेष अंक
+
मुफ्त प्रीमियम डबल बेड शीट



मूल्य ₹50



ग्राहक प्रति
कृपया मेरी प्रति सुरक्षित करें

पाञ्चजन्य	सामान्य डाक	एक वर्ष (52 अंक*) ~~₹2600~~	₹1500 + मुफ्त उपहार एक डबल बेडशीट	42% छूट
आर्गेनाइजर	सामान्य डाक	एक वर्ष (52 अंक*) ~~₹2600~~	₹1500 + मुफ्त उपहार एक डबल बेडशीट	42% छूट
पाञ्चजन्य+आर्गेनाइजर	सामान्य डाक	एक वर्ष (52 अंक*) ~~₹5200~~	₹2500 + मुफ्त उपहार दो डबल बेडशीट	52% छूट

*साथ में 4 विशेष अंक

पंजीकृत डाक के लिए ₹1000 अतिरिक्त चुकाएं

पहला नाम | मध्य नाम | अंतिम नाम

मोबाइल नं. ______ ई-मेल ______

पत्रिका प्राप्त करने का पता ______

पिन कोड ______ शहर ______ राज्य ______



Paytm No. 8143232814

Bharat Prakashan (Delhi) Ltd. Ref No.: .... Date: .... For ₹............................

ग्राहक सदस्यता फार्म

कार्यालय प्रति

क्रमांक: ....

पहला नाम | मध्य नाम | अंतिम नाम

मोबाइल नं. ______ ई-मेल ______

पत्रिका प्राप्त करने का पता ______

पिन कोड ______ शहर ______ राज्य ______

Bharat Prakashan (Delhi) Ltd. Ref No.: .... Date: .... For ₹............................

नोट : प्रतिक्रिया प्रपत्र के लिए पन्ना पलटें

Subscribe Online: www.panchjanya.com and www.organiser.org or Call 8143232814 or e-mail: support@bpdl.in



बात भारत की

पाञ्चजन्य

(साप्ताहिक)

पाठकों की राय

प्रिय पाठको!

हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनेक पाठक निरंतर सुझाव भेजते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि '**पाञ्चजन्य**' में प्रकाशित होने वाली सामग्री पर अधिक से अधिक पाठकों की प्रतिक्रिया मिलती रहे। कृपया नीचे दिए गए प्रपत्र को भरकर ईमेल, व्हाट्सएप या डाक के माध्यम से प्रेषित करें।

नामः	आयुः	फोनः
स्थानः	ई-मेलः	

आप इस प्रपत्र को **editor.panchjanya@bpdl.in** पर ईमेल अथवा इसका फोटो लेकर 8143232814 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप पत्रिका के वितरण संबंधी शिकायत भी भेज सकते हैं।

1. पाञ्चजन्य में प्रकाशित सामग्री आपको कैसी लगती है?
   अ) अति उत्तम   ब) अच्छी   स) औसत   द) स्तरहीन

2. पाञ्चजन्य में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?

3-वर्तमान में प्रकाशित हो रही विविध सामग्री के साथ आप पाञ्चजन्य में और क्या पढ़ना चाहते हैं?

4-पाठक के नाते आप पाञ्चजन्य से कितने समय से जुड़े हुए हैं?

5-कोई अन्य सुझाव

भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड

द एड्रेस

प्लॉट नंबर- 4बी, डिस्ट्रिक सेंटर, मयूर विहार, फेज-1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091

आर.एन.आई. पंजीकृत संख्या 32543/1977
15-21 नवम्बर, 2021 (13 नवम्बर को प्रकाशित, पृष्ठ-52)

पाञ्चजन्य साप्ताहिक

दिल्ली पोस्टल क्र.डी.एल.(सी.)-01/1102/2021-23 एल.पी.सी. दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली-06
लाइसेंस क्र.यू. (सी.)-87/2021-23 अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति 13/15-11-2021